वर्ष : 23 अंक : 1 (80वाँ अंक) जनवरी-मार्च, 2018

विचार

पिछड़े क्षेत्रों के लोगों तक सार्वजनिक योजनाओं की पहुँचः

'लोगों की मजबूत आवाज'

यूरोपीय संघ

उन्नति
UNNATI

- **संपादकीय** **3**
- सार्वजनिक योजनाओं तक पहुँच में सुधार के लिए रणनीतियां:
  मुख्य व्याख्यान: 'मांग पैदा करने के लिए लोगों के समूहों को मजबूत करना' **6**
- सार्वजनिक सेवाओं तक टिकाऊ पहुंच बनाने के लिए समूहों को मजबूत करना **14**
- 'सेवा' शक्ति केंद्र (एसएसके) के अनुभव **10**
- झारखंड में पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली के लिए पहल **17**
- भारत के पांच पिछड़े जिलों में मांग पैदा करने के लिए डीपीओ को मज़बूत करना **20**
- मांग पैदा करने के लिए समूह का निर्माण **22**
- चर्चा और अध्यक्ष की टिप्पणी **23**
- 'महिला किसान सम्मेलन' **28**
- 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के संदर्भ में सम्मेलन **30**

संपादकीय

सार्वजनिक कार्यक्रमों तक बेहतर पहुंच के लिए युवाओं की डिजिटल साक्षरता में वृद्धि

भारत जैसे देश में जहां अधिकांश आबादी गरीब है, वहां समुदाय अपने अस्तित्व के लिए सार्वजनिक योजनाओं के प्रभावी वितरण पर बहुत अधिक निर्भर हैं। पिछले सात दशकों से केंद्रीय और राज्य सरकारों ने मुख्य रूप से शिक्षा, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक संरक्षा और आजीविका से संबंधित बुनियादी मानव विकास संकेतकों को पूरा करने की तर्ज पर गरीबी उन्मूलन और सामाजिक विकास के लिए काफी सार्वजनिक योजनाएं तैयार की हैं। अधिकांश आबादी को अपने वे हक प्राप्त करने में बाधाएं आती हैं जो उन्हें गरीबी के जाल या गरीबी के दुष्चक्र से बाहर उठाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हक प्राप्त नहीं होने के कारणों में डिजाइन में अंतर्निहित बाधाओं, कार्यान्वयन बाधाओं और बजटीय आवंटन को भी जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। यह एक वैश्विक घटना है। जैसा कि ILO द्वारा 'विश्व सामाजिक संरक्षण रिपोर्ट' 2014-15 में बताया गया है कि केवल 27 प्रतिशत आबादी को सार्वजनिक योजनाओं के बारे में सूचित किया जाता है जिनकी वे हकदार हैं। यह भारत जैसे देश के लिए अनौपचारिक स्रोतों से अनुमानित 10 प्रतिशत से भी कम हो सकता है।

अनुभव से पता चलता है कि ग्रामीण व्यवस्था में जीवन यापन के लिए औसत पांच व्यक्तियों के गरीब परिवार को सालाना 70,000 रुपये की आवश्यकता होती है। यदि ऐसे परिवार को सरकारी योजनाओं के लाभों का हक मिल सके, तो यह सालाना कम से कम दो - तीन लाख हो सकता है। तब प्रश्न उठता है कि ऐसी संभावनाओं को किस तरह से प्रभावित किया जाता है? आमतौर पर, इन लाभों को प्राप्त करने और किसी विशेष योजना के लिए योग्यता साबित करने की ज़िम्मेदारी लाभार्थी पर होती है। सीमित साक्षरता और गतिशीलता वाले कमजोर वर्ग अधिकांश योजनाओं के लाभों को प्राप्त करने में प्रतिबंधित महसूस करते हैं जब तक उन्हें उनके दरवाजे पर नहीं पहुंचाया जाए। इसके अलावा, उनकी शिकायतों को हल नहीं किया जा रहा है, बार-बार लाभार्थी अधिकार प्राप्त करने में असहाय, अपमानित और हतोत्साहित महसूस करता है।

सार्वजनिक सेवाओं को प्राप्त करने में आने वाली बाधाओं को कम करने के लिए और आखिरी लाभार्थी तक पहुंचने के लिए इंटरनेट संचार प्रौद्योगिकी (ICT) का उपयोग करके दो दशकों पहले देश के चयनित राज्यों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक शासन (ई-गवर्नेंस) की अवधारणा पेश की गई थी। इसे दो साल पहले केंद्र सरकार द्वारा एक बड़े रूप में लॉन्च किया गया था, जिसका उद्देश्य नागरिकों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाकर सभी सेवाओं को सुविधाजनक, कुशल और पारदर्शी तरीके से उपलब्ध कराना है। दूर-दराज के स्थानों में रहने वाले समुदायों के बीच कनेक्टिविटी-प्रसार और पहुंच के अवसरों के साथ मिलकर कंप्यूटर के फैलाव रूप में सुविधाजनक ईको-सिस्टम सामने आया है।

2006 में लॉन्च किए गए भारत सरकार की 'राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस प्लान (NeGP)' ने नागरिकों को अपने घरों पर किफायती लागत पर और स्थायी तरीके से सरकारी सेवाएं प्रदान करने की कल्पना की है। NeGP ढांचे के तहत इसे हासिल करने के लिए, सेवाओं और प्रौद्योगिकी तक पहुंच प्रदान करने के साधनों के साथ-साथ निजी और सरकारी सेवाओं के प्रावधानों के साथ नागरिकों की सहायता करने का कार्य मानते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में अब तक 99,000 से अधिक 'कॉमन सर्विसेज सेंटर (CSC)' स्थापित किए गए हैं। CSC गांव स्तर के उद्यमियों (VLE) द्वारा चलाए जाते हैं। सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) पसंदीदा मॉडल है। इन केंद्रों के कामकाज की निगरानी और पर्यवेक्षण और नागरिकों को सेवाएं देने के लिए VLE के लिए आवश्यक क्षमता पैदा करने के लिए CSC ई-गवर्नेंस सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नामक एक विशेष प्रयोजन वाहन (SPV) की स्थापना की गई है।

देश के अधिकांश राज्यों में सामान्य सेवा केंद्र (कॉमन सर्विस सेन्टर - CSC) स्थापित के गए हैं, जो आमतौर पर ग्राम पंचायत परिसर के भीतर होते हैं और वे अपने आसपास के क्षेत्र में 6 से 7 गांवों की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। उनके पास विभिन्न प्रबंधन तंत्र हैं और उनके विभिन्न नाम हैं। झारखंड में उन्हें प्रज्ञा केंद्र कहते हैं और राजस्थान में ई-मित्र नामक ग्राम उद्यमी द्वारा प्रबंधित अटल सेवा केंद्र कहते हैं। समुदाय ऑनलाइन यात्रा टिकट, वित्तीय उत्पाद, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाणपत्र, मृत्यु और जन्म प्रमाण पत्र जैसी बुनियादी सेवाएं प्राप्त करने में सक्षम हुआ है। CSC ग्राम पंचायत स्तर पर सूचना केंद्र और सहायता डेस्क के रूप में कार्य करते हैं और योजनाओं की स्थिति का पता करने के लिए सक्षम बनाते हैं। इसने लाभार्थियों को अपने आवेदनों को डेस्क से डेस्क पर और ब्लॉक से जिला स्तर तक पता करते रहने की परेशानी को कम कर दिया है। सामान्य सेवा केंद्रों की प्रभावशीलता केंद्र या राज्य की सेवाओं/योजनाओं से सीधे संबंध है जो उनके माध्यम से ऑनलाइन कार्य-व्यवहार (लेन-देन) के लिए उपलब्ध कराई जाती हैं। इस मोर्चे पर राज्यों में भिन्नता है। कवरेज के मामले में सफलता का रूपांतरण नागरिकों को सेवा की गहराई और गुणवत्ता में नहीं किया गया है। आम सेवा केंद्र आय अर्जित करने के लिए उपयोगिता सेवाओं पर निर्भर रहते हैं। सरकार से नागरिक के मूल्यवर्धित कार्य-व्यवहार, जैसे सूचना, ऑनलाइन आवेदन, भरे हुए आवेदनों की ट्रैकिंग, शिकायतों का पंजीकरण, विभिन्न केंद्रों/राज्य प्रायोजित कल्याण योजनाओं, स्वास्थ्य और कृषि संबंधी जानकारी, आदि के लिए निवारण की स्थिति की कमी के कारण, ग्राम स्तर के कंप्यूटर उद्यमियों को अपने मुनाफे को अधिकतम करने के अन्य साधनों का सहारा लेना पड़ेगा। सरकार को सामान्य सेवा केंद्रों के माध्यम से सरकार से अधिक से अधिक मूल्यवर्धित नागरिक सेवाओं को प्रदान करने के लिए कदम उठाने की जरूरत है। राजस्थान ने सामान्य सेवा केंद्र स्तर पर कार्य-व्यवहार के लिए अधिकांश योजनाएं खोली हैं। कई राज्यों में, सामान्य सेवा केन्द्रों को योजनाओं से संबंधित ऑनलाइन सेवा प्रदान करने की क्षमता से अच्छी तरह से संसाधित/सुसज्जित नहीं किया गया है। सामान्य सेवा केंद्रों को नागरिकों के लिए प्रभावी और सार्थक होने के लिए स्पष्ट रूप से बनाए चार्टरों के साथ सेवा स्तर मानकों की गारंटी देना महत्वपूर्ण है।

अनुभव से पता चलता है कि 'राजस्थान सम्पर्क' और 'PG पोर्टल' जैसे ऑनलाइन पोर्टलों ने नागरिकों को जटिल और लंबित मामलों के लिए अपनी शिकायतें ऑनलाइन दर्ज करने के लिए सशक्त बनाया है। प्रशासन में लोगों का विश्वास कुछ हद तक बहाल कर दिया गया है क्योंकि शिकायतकर्ताओं को गुमनाम रखा जाता है और कई मामलों में भी शिकायतों का निवारण किया गया है।

शहरी और ग्रामीण लोगों, अमीरों और गरीबों और पुरुषों और महिलाओं और हाल के वर्षों में स्मार्ट फोन के बढ़ते कवरेज के बीच इंटरनेट तक पहुंच में डिजिटल विभाजन और असमानताओं का संज्ञान लेते हुए कई राज्यों ने नागरिक सेवाओं/लेनदेन के लिए सरकार का सहयोग करने और अनुप्रयोगों की स्थिति को ट्रैक करने में मदद करने के लिए मोबाइल ऐप लॉन्च किए हैं जिन्हें आसानी से प्लेस्टोर से डाउनलोड किया जा सकता है। राजस्थान में, ऐप को 'राजस्थान एप्लिकेशन स्थिति या एपस्टैटस' कहा जाता है और बिहार में, इसी तरह के ऐप को 'ई-लाभार्थी' कहा जाता है।

हम यह नहीं कहना चाहते हैं कि आमने-सामने के शिकायत निवारण तंत्र की उपेक्षा की जाए। जन सुनवाई या राजस्थान में रात्रि चौपाल जैसे आमने-सामने बैठकर शिकायतों को हल करने की प्रासंगिकता और महत्व जवाबदेही को मजबूत करने के लिए बहुत महत्वपूर्ण और शक्तिशाली तंत्र हैं। राजस्थान में एकीकृत शिकायत निवारण प्रणाली है जिसमें नागरिकों के नामित वेब पोर्टल पर या टोल फ्री टेलीफोन नंबर के माध्यम से अपनी शिकायतों को पंजीकृत करने के अलावा, आवधिक जन सुनवाई (सुनवाई के अधिकार अधिनियम 2012 में प्रावधान के तहत) या किसी भी सरकारी अधिकारी के सामने की गई शिकायत को दर्ज करना होता है और राजस्थान सम्पर्क के माध्यम से निगरानी की जाती है और पूरी गंभीरता के साथ निपटारा किया जाता है।

बेहतर शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए, 'सार्वजनिक सेवा गारंटीकृत डिलिवरी अधिनियम, 2011' और 'सुनवाई अधिकार अधिनियम, 2012' जैसे प्रगतिशील कानूनों का लाभ उठाया जा सकता है। शिकायत निवारण के लिए MGNREGA 2005 में शामिल

सामाजिक ऑडिट का तंत्र ऑनलाइन उपलब्ध लाभार्थी ट्रैकिंग और सत्यापन के विकल्प के साथ राष्ट्रव्यापी तंत्र भी है। कई नागरिक समाज संगठनों ने सार्वजनिक सेवाओं का लाभ उठाने के लिए लाभार्थी को प्रेरित करने के लिए एप्लिकेशन विकसित किए हैं। 'वेल्थंगरहिल्फ' ने माताओं के लिए मोबाइल टैबलेट विकसित किया है, एक मोबाइल एप्लिकेशन जो झारखंड में आशा कार्यकर्ताओं को गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों को सुरक्षित डिलीवरी तक रिकॉर्ड करने में मदद करता है और अब राज्य सरकार द्वारा इसे आगे बढ़ाया जाएगा। 'नंद और जीत खेमका फाउंडेशन'ने एक मोबाइल टैबलेट स्वास्थ्य स्लेट विकसित की है जो बीमारियों की रोकथाम, देखभाल और रेफरल के लिए नैदानिक परीक्षण करने के लिए फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कर्मियों (ANM और आशा कार्यकर्ताओं) को सक्षम बनाता है। कार्यान्वयन के दो साल बाद, यह पाया गया कि परियोजना पंचायतों में स्वास्थ्य जोखिम के कारण मातृ रोग का एक भी मामला दर्ज नहीं किया गया।

हाल ही में राजस्थान में गुणवत्ता सेवाओं को प्राप्त करने के लिए ग्राम पंचायत स्तर पर वन स्टॉप सर्विस डिलीवरी टच स्क्रीन कियोस्क सॉल्यूशन के रूप में ईमित्र प्लस सर्विस और विशेष रूप से जनजातीय क्षेत्रों में युवाओं के बीच ई-लर्निंग को बढ़ावा देने के लिए 'ज्ञान दर्पण' उपकरण लॉन्च किया गया था। ईमित्र प्लस आवेदकों/शिकायतकर्ताओं या योजना लाभार्थियों द्वारा स्वयं के लिए एक गांव स्तर के उद्यमी की आवश्यकता के बिना मामूली शुल्क के साथ अपने लेनदेन को पूरा करता है। हालांकि, ग्रामीण उपयोगकर्ता में ई-साक्षरता के वर्तमान स्तर को देखते हुए, प्रत्येक कियोस्क में दो ई-सखी को विकसित करने का निर्णय लिया गया है जिन्हें सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रशिक्षित किया जाएगा और प्रौद्योगिकी के साथ उपयोगकर्ताओं का सहयोग किया जाएगा। उनकी प्रतिपूर्ति और अन्य विवरणों की व्यवस्था अभी तय की जा रही है। इस तरह की पहल खामियों के बिना सार्वजनिक सेवाओं की त्वरित डिलीवरी के लिए एक लंबा सफर तय करेगी।

सभी राज्य सरकारों द्वारा तेज़ी से सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित करने के लिए अभिनव तंत्र शुरू करने और प्रयासों को बढ़ाने के लिए सतत विकास लक्ष्यों को प्राप्त करना जरूरी है, विशेष रूप से गरीबी समाप्त करने, खाद्य सुरक्षा और बेहतर पोषण, स्वस्थ जीवन सुनिश्चित करने और सभी उम्र के लिए सभी तरह के कल्याण को बढ़ावा देने के संबंध में समावेशी और न्यायसंगत गुणवत्ता शिक्षा सुनिश्चित करें और सभी के लिए आजीवन सीखने के अवसरों को बढ़ावा दें और लिंग समानता प्राप्त करें और सभी लड़कियों और महिलाओं को सशक्त बनाएं। ऐसी पहलों के लिए एक शर्त यह है कि सबसे पहले महिलाओं, गरीबों, देश के कम साक्षरता वाले क्षेत्रों और विकलांग व्यक्तियों के लिए एकाधिक और अतिव्यापी बाधाओं पर ध्यान केंद्रित करने वाले डिजिटल विभाजन को कम किया जाए और समुदाय को इन स्वयं सेवा केंद्रों तक पहुंचने में सक्षम होने के लिए लिए युवाओं की ई-साक्षरता में वृद्धि की जाए। ■

सार्वजनिक योजनाओं तक पहुँच में सुधार के लिए रणनीतियां

यह 3 अगस्त 2017 को अहमदाबाद में 'यूरोपीय संघ' (ईयू) द्वारा समर्थित 'सार्वजनिक योजनाओं की जानकारी की पहुँच में सुधार' नामक परियोजना के तहत पर आयोजित एक परामर्श रिपोर्ट का हिस्सा है। यह साझेदारों की रिपोर्टिंग मीट का भाग नहीं है, लेकिन सार्वजनिक कार्यक्रमों को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए रणनीतियों पर सबक सीखना है। इस परामर्श को तीन प्रमुख सत्रों में विभाजित किया गया था:

1. मांग पैदा करने के लिए लोगों के समूहों को मजबूत करना;
2. जवाबदेही के लिए जनता को शामिल करना और
3. सार्वजनिक योजनाओं तक पहुंच में नवाचार।

कुल 13 पेपर प्रस्तुत किये गये थे - 8 पेपर 'यूरोपीय संघ' समर्थित परियोजनाओं के अनुभवों पर आधारित थे और 5 समान विषय और मुद्दों के आसपास के अनुभवों वाले अन्य गैर-सरकारी संगठन भागीदारों के थे।

इसमें 78 प्रतिभागियों ने भाग लिया जिनमें मुख्य वक्ता प्रो. घनश्याम शाह, सत्र अध्यक्ष, प्रो. नवदीप माथुर, श्री अच्युत दास और डॉ. तारा नायर, 14 यूरोपीय संघ (ईयू) समर्थित परियोजना साझेदारों के 11 प्रतिनिधि और गैर-सरकारी संगठनों और शैक्षिक संस्थानों के प्रतिनिधि शामिल थे।

'विचार' के इस अंक में उद्घाटन व्याख्यान और पहले विषयगत सत्र, 'मांग पैदा करने के लिए लोगों के समूहों को मजबूत करना' में प्रस्तुत लेखों को शामिल किया गया। दूसरे दो सत्रों को विचार के अगले अंक में शामिल किया जाएगा। हमें यकीन है, विचार-विमर्श से तैयार किए गए कागजात और नोट्स सार्वजनिक कार्यक्रमों को प्रभावी ढंग से अंतिम स्थान तक पहुंचाने के लिए कार्यान्वयन रणनीतियों के डिजाइन और सुधार करने में मदद करेंगे। सुश्री गीता शर्मा और सुश्री सुनेत्रा देशपांडे ने परामर्श में प्रस्तुत प्रस्तुतियों और चर्चाओं का दस्तावेजीककरण किया है।

मुख्य व्याख्यानः
मांग पैदा करने के लिए लोगों के समूहों को मजबूत करना

प्रोफेसर घनश्याम शाह ने परामर्श में शामिल होने पर खुशी जाहिर की, विशेष रूप से यह जानकर कि यूरोपीय संघ के परियोजना साथी सार्वजनिक कार्यक्रमों के बारे में जानकारी तक पहुंच में सुधार के दायरे से आगे निकल गए हैं और सार्वजनिक कार्यक्रमों और योजनाओं को गरीबों तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं और लाभ पहुंचाना सुनिश्चित किया है। यह एक ताकत है जो इस क्षेत्र से आई है।

आइए हम पहले समझें कि सार्वजनिक सुरक्षा से हमारा क्या मतलब है और यह क्यों महत्वपूर्ण है। सुरक्षा केवल खाद्य सुरक्षा के बारे में नहीं है, जो कि जीवन के लिए न्यूनतम आवश्यकता है। अस्तित्व के लिए स्वास्थ्य सुरक्षा भी आवश्यक है। आज, अधिकांश लोगों, न केवल गरीब, बल्कि मध्यम वर्ग और यहां तक कि उच्च मध्यम वर्ग में भी असुरक्षा की भावना है। हमारे पैदा होने से लेकर बुढ़ापे तक हमारी सहज प्रवृत्ति किसी न किसी प्रकार की सुरक्षा प्राप्त करने की होती है। जब हम काम करना शुरू करते हैं और जानते हैं कि हमारा काम अस्थायी और संविदात्मक है, तो हम अनिश्चित और असुरक्षित महसूस करते हैं और यह हमारे व्यक्तित्व और कार्य को प्रभावित करता है। असुरक्षा और अनिश्चितता की स्थिति में, हमें पीछे हटना पड़ता है। 'पीछे हटना' मौलिक है और यह समाज में निरंतर तनाव

और हिंसा - एक अलग तरह की हिंसा में निरंतर वृद्धि करता है। अगर हम आत्मनिरीक्षण करते हैं, तो हम महसूस करेंगे कि जैसा समाज हमने बनाया है, उसमें केवल सामाजिक डार्विनवाद का सिद्धांत ही काम करता है। अगर किसी के पास धन और शक्ति है तो वही जीवित रहता है और बाकी सभी को पीछे हटना पड़ता है।

यदि हम मानते हैं कि सुरक्षा महत्वपूर्ण है, तो हमें खुद से पूछना चाहिए, 'नागरिक समाज के कार्यकर्ताओं के रूप में हमारा दृष्टिकोण क्या होना चाहिए? हमारा जानकारी तक पहुंच से क्या मतलब है और इसकी आवश्यकता क्यों है?' अगर हमें ये स्पष्ट हैं, तो हमारी रणनीति बहुत स्पष्ट होगी। जानकारी तक पहुंच आत्मविश्वास बढ़ाने और सामूहिक पैरवी को बढ़ाने और उसे मजबूत करने से जुड़ी हुई है। यह उस कक्षा में जानकारी देने के बारे में नहीं है जहां छात्रों को इसे याद करना है और भूल जाना है। आज, हर गांव में आप योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और फिर भी योजनाएं नहीं पहुंच पाई हैं क्योंकि लोग मुखर नहीं हैं। यह महत्वपूर्ण है कि हम योजनाओं के विवरण को समझें, उन्हें सरल करें और लोगों को ऐसी जानकारी दे जो उन्हें सशक्त महसूस करवा सके। यह महत्वपूर्ण है कि उन्हें लगे कि वे जानते हैं और वे दावा कर सकते हैं। हमें अपने आप से यह पूछने की जरूरत है कि 'किस प्रकार की जानकारी को प्रसारित करने की आवश्यकता है और हमें लोगों को कैसे शामिल करना चाहिए ताकि उनके अधिकारों की मांग बढ़ जाए?' मांग केवल योजनाओं के विस्तार के बारे में नहीं है; इसका मतलब यह है कि लोग उन लोगों से सवाल करने में सक्षम हो सकें जो प्रशासन के लिए जिम्मेदार हैं और योजनाओं के संचालन के लिए जिम्मेदार हैं।

हमें अपने आप से यह पूछने की भी जरूरत है, 'क्या हम लोगों को लाभार्थियों के रूप में या नागरिक के रूप में या साझेदारों के रूप में व्यापक रूप से देख रहे हैं?' ये योजनाएं 'माई-बाप' द्वारा नहीं दी जा रही हैं। नागरिकों के रूप में लोगों को इन योजनाओं का अधिकार है। सरकार जो कुछ भी कर रही है, वह निश्चित रूप से उदारता या 'उपकार' नहीं है, लेकिन यह सरकार के शासन की जिम्मेदारी है। जब यह स्पष्ट हो जाएगा, तो मांग और पहुंच के लिए हमारा दृष्टिकोण अलग होगा और हमारा दावा भी अलग रूप में होगा। यदि हम इस दृष्टिकोण का उपयोग करते हैं, तो इसके लिए बहुत प्रयास की आवश्यकता हो सकती है। हमें लोगों से उनके सांस्कृतिक संदर्भ में बात करना होगा और बहुत कल्पनाशील होना होगा। यह प्रयास इस मायने में लायक होगा कि अगली बार हमें इसे करने की ज़रूरत नहीं होगी। लोग स्वयं इसे आगे ले जाएंगे। योजनाएं बढ़ जाएंगी और लोगों की मांग आ जाएगी और जब लोग मांग करना शुरू करेंगे, तो इससे दबाव बढ़ जाएगा। जो भी शासन कर रहा है, भले ही कोई भी राजनीतिक वर्ग हो, न केवल चुनाव के दौरान, बल्कि अपने स्वयं के राजनीतिक अस्तित्व के लिए भी लोगों को संतुष्ट करना होगा।

समाज द्वारा बनाए गए दबावों की वजह से ही कई योजनाएं शुरू की गई हैं। सभी प्रारंभिक भूमि सुधार लोगों के दबाव के परिणाम स्वरूप ही हुए थे। भेदभाव से संबंधित सभी अधिनियम, चाहे लिंग या जाति से संबंधित क्यों न हो, पारित नहीं किये गये होते अगर महिलाओं द्वारा मांग नहीं की जाती या दलितों या आदिवासियों द्वारा दावा नहीं किया जाता। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि लोग को सत्तारूढ़ वर्ग को उनसे नागरिक के रूप में व्यवहार करने और उनसे साझेदारी करने और उन्हें अधिकार के रूप में योजना देने के लिए लगातार मजबूर करते रहें।

तीसरा, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, चिरंजीवी योजना और पेंशन जैसी सभी योजनाएं उस बड़े वादे का एक हिस्सा हैं, जो भारतीय संविधान ने अपने लोगों से किया है। कार्यकर्ता के रूप में, यदि हम स्वास्थ्य पर काम कर रहे हैं, तो हम खुद को एक या दो योजनाओं तक सीमित नहीं रख सकते। हालांकि हम कुछ योजनाओं पर दूसरों की तुलना में अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि सभी स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं नागरिक के स्वास्थ्य के अधिकार में योगदान करती हैं। हम व्यक्ति के अधिकार पर इस बड़े फोकस के प्रति उदासीन नहीं रह सकते। इसी तरह, यदि हम शिक्षा के अधिकार पर काम कर रहे हैं, तो हमें सार्वजनिक स्कूलों के बढ़ते जमाव, शिक्षकों की कमी या निजी स्कूलों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बच्चों के लिए 25 प्रतिशत आरक्षण के प्रावधान के गैर-कार्यान्वयन जैसे मुद्दों से चिंतित होना होगा। ऐसे मुद्दे इसलिए उभरे हैं क्योंकि हम सरकार पर दबाव बनाने में नाकाम रहे हैं। भारतीय संविधान आम स्कूलों के बारे में चर्चा करता है और हम इसके बारे में भूल गए हैं। लगातार, हम एक अलग दिशा में चले गए हैं और अब हम उन बच्चों को 25 प्रतिशत आरक्षण देने से संतुष्ट हैं, जो निजी स्कूलों में प्रवेश नहीं कर सकते। कुछ बाधाओं के कारण, हम अपने ध्यान को सीमित करते हैं।

लेकिन जब हम किसी गांव में काम कर रहे हैं और लोगों के साथ काम कर रहे हैं, तो हमें संपर्क बनाने की जरूरत है और चीजों को समग्रता में देखने की जरूरत है।

सामूहिक सौदेबाजी और जवाबदेही के लिए जानकारी तक पहुंच के पूरे विचार का विस्तार करने की आवश्यकता है। यदि इस परियोजना के अनुभव से कोई भी रणनीति विकसित की जा सके, तो यह सही दिशा में एक कदम होगा। यह एक बड़ा परिवर्तनकारी विकास नहीं भी हो, तो भी यह एक संतोषजनक परिणाम होगा और परियोजना को जिम्मेदारी की भावना से लागू किया जाएगा। प्रोफेसर शाह ने आह्वान किया कि आइए हम अपने आपको संवेदनशील बनाएं और हमारे साथी कार्यकर्ताओं को संवेदनशील बनाएं। अगर हम अपने काम को एक सामान्य परियोजना के रूप में नहीं, परन्तु उससे बहुत अधिक आगे तक देखेंगे, तो हम बहुत कुछ प्राप्त कर सकते हैं।

चर्चा

1. हमें उन लोगों की असहायता महसूस करनी चाहिए जो हर रोज असुरक्षित महसूस कर रहे हैं क्योंकि कार्यक्रम उन तक नहीं पहुंच रहे हैं। जब हम दूरदराज के गांव में एक गरीब घर में किसी व्यक्ति की असहायता को मानते हैं और महसूस करते हैं, तो हम इसके बारे में जरूर कुछ कर सकते हैं।
2. सामूहिक सौदेबाजी के लिए जानकारी तक पहुंचने के लिए संपर्क बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। जानकारी तक पहुंच सिर्फ एक माध्यम है और इसे लोगों द्वारा ताकत देने, सशक्तिकरण और दावा करने में सहायक होना चाहिए।
3. हमें नागरिकों के अधिकारों का गठन करना है क्योंकि लोग अब लाभार्थी नहीं हैं। हमें इस तरह से काम करने की आवश्यकता है जिससे नागरिक मांग करें ताकि सत्तारूढ़ व्यवस्था प्रदान करे। सार्वजनिक कार्यक्रम सत्तारूढ़ शासन की सहानुभूति के आधार पर नहीं आए हैं बल्कि नागरिक समाज और लोगों के आंदोलनों के दबाव के कारण आए हैं।
4. जब तक वोट बैंक की राजनीति का आयाम रहेगा, तब तक सार्वजनिक योजनाएं सुलभ नहीं होंगी। जिस योजना को अधिक मत मिलेंगे, राजनीतिक व्यवस्था और नौकरशाही द्वारा उसे ही ज्यादा महत्व दिया जाएगा। सामूहिक सौदेबाजी एक सीमा तक ही कार्य करेगी जब तक कि ये समूह राजनीतिक क्षेत्र में प्रवेश न करें; इसलिए, सिविल सोसाइटी के रूप में हमारी भूमिका यह है कि किसी भी तरह यह संभाषण वास्तविक जीवन में लाएं ताकि सामान्य लोगों (नागरिकों) के पास कुछ सवाल हों और वे सामाजिक ऑडिट और जवाबदेही के मुद्दों पर विचार करना शुरू करें। (अच्युत दास, अग्रगामी)
5. आजकल, सिकुड़ते स्थान के कारण सीएसओ बहुत असुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस तरह के परामर्श से एकजुटता बढ़ाने में मदद मिलेगी और इस पर मनन होगा कि सीएसओ के रूप में, हम नागरिक स्थान के भीतर अपनी जगह कैसे बढ़ा सकते हैं। जो इस क्षेत्र में काम करते हैं, वे जानते हैं कि मांग और आपूर्ति के बीच एक बड़ा अंतर है, जो लोगों को बिखेरता है; मांग 100 है और आपूर्ति 5 है। जब तक बजट आवंटित नहीं किया जाता, तब तक नागरिक का स्थान बरकरार रखने के लिए चुनौती बनी रहेगी। (सुकांत सरकार, प्रदान)
6. बड़े समाज के लिए यह समझना महत्वपूर्ण है कि योजनाएं धर्मार्थ नहीं हैं, वे एक नागरिक का अधिकार हैं और समाज का एक हिस्सा ऐसा है जिसे केवल इन योजनाओं के जरिए ही संबल प्रदान किया जा सकता है। एक अध्ययन के मुताबिक, ग्रामीण गरीबों में 8-10 फीसदी अत्यधिक कमजोर होते हैं। वर्तमान में, सरकार और शैक्षणिक संस्थानों में एक प्रवृत्ति सामाजिक उद्यमिता को बढ़ावा देने की है। जो लोग कमजोर हैं उन्हें प्रशिक्षण के लिए नहीं भेजा जा सकता क्योंकि वे उम्र, कामकाजी परिस्थितियों, सीखने की अपनी क्षमताओं, आदि जैसे कारकों के कारण विवश हैं। (राजेश भट्ट, स्वपथ ट्रस्ट)
7. आज एक विशेष प्रकार की परिस्थितियां हैं और वे काफी हद तक राजनीतिक हैं। अधिकारों पर आधारित कानून का एक पूरा दौर था। कानून क़ानून की पुस्तक में हैं और उनके माध्यम से कई चीजों तक पहुंच की आवश्यकता है। लेकिन राजनीतिक व्यवस्था पूरी तरह से इसका विरोध कर रही है - या तो इसे खत्म करने में लगी हुई है या यह बाज़ार तंत्र की तरफ जा रही है। लोगों को नागरिकों के रूप में अधिकार दिया गया था और उन्हें बताया गया कि यह उनका अधिकार था, लेकिन अधिकार का उपयोग करने के लिए एक शक्ति संघर्ष शामिल है, इसके लिए सुविधा की आवश्यकता है। यह भूमिका गैर-सरकारी संगठन या राजनीतिक दल या कुछ ग्राम आधारित संगठनों द्वारा निभाई गई थी, लेकिन इसके वांछित परिणाम प्राप्त नहीं हो सके। आज, जो कुछ हो रहा है, वह उस खाई को पाटने के खिलाफ हो रहा है जो बदलाव ला सकता है। आप राजनीतिक

दलों से बात करें तो उन्हें कोई दिलचस्पी नहीं है। उन्होंने उसे कहीं न कहीं से वोट से अलग कर दिया है। यदि आप एनजीओ सेक्टर में बात करते हैं, तो बहुत से लोग अपने स्वयं के अस्तित्व के बारे में काफी चिंतित हैं और ऐसे कुछ नहीं करना चाहते है जिसे राजनीतिक संघटन के रूप में देखा जाए। यह उन लोगों के लिए एक चुनौती है जिनके लिए यह उनके काम का एक अभिन्न अंग है; जब तक सामूहिक सौदेबाजी नहीं होती तब तक आप सार्वजनिक सेवा प्रदान नहीं कर सकते। जो लोग प्रशिक्षण कार्यक्रमों में आते हैं, जो गरीब हैं, जो एसएचजी में आते हैं, वे वही होते हैं और वे वही हैं, जिन्हें इन योजनाओं का उपयोग करना है। ऐसे समूह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि लोग पहुंच प्राप्त करें और उन्हें मंच भी मिले जो संगठन के लिए खतरा हुए बिना बहुत ही निर्णायक और महत्वपूर्ण है? अगर संगठनों को खतरा महसूस होता है तो वे इसमें शामिल नहीं होंगे। यह वास्तव में संवैधानिक ढांचे और कानूनी ढांचे का हिस्सा है। उदाहरण के लिए, सामाजिक ऑडिट कानून का एक हिस्सा है; फिर भी यदि आप वास्तव में उस मंच के असली सामाजिक ऑडिट में शामिल होते हैं तो बहुत सारी प्रतिक्रियाएं होंगी। तो सवाल यह है कि आप उन संस्थाओं का निर्माण कैसे करेंगे जो इस तरह के संगठनों पर प्रतिक्रिया नहीं लाएंगे लेकिन सुविधाप्रदाताओं से स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रहेंगे? (निखिल डे, एनसीपीआरआई और एमकेएसएस)

8. हमारी ज्यादातर बहस और हमारे कार्यकलाप लोगों के रोज़ाना के अस्तित्व को बनाए रखने के लिए उनकी सामूहिक क्षमता का निर्माण करने पर है। यहां चर्चित रणनीतियां लोगों की ताकत बढ़ाने पर केन्द्रित हैं, लेकिन शायद यह भी महत्वपूर्ण है कि सार्वजनिक कार्यक्रमों और योजनाओं तक पहुंचने की जटिलताओं को कम करने की दिशा में काम करने के लिए कानून निर्माताओं या नीति निर्माताओं का विश्वास भी निर्मित किया जाए। (नीता हार्डीकर, आनन्दी)

प्रो. घनश्याम शाह की समापन टिप्पणी

प्रो. शाह ने कहा कि सभी उठाए गए सवाल और की गई टिप्पणियां एक-दूसरे से जुड़े हुए हैं। अच्युत और निखिल की टिप्पणियों का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि सब कुछ राजनीति से संबंधित है या राजनीति के बारे में है। उन्होंने ज़ोर दिया कि एनजीओ को 'प्रोजेक्ट' मोड से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। परियोजना से संबंधित सब कुछ फंडिंग एजेंसी द्वारा तय किया जाता है। लोगों को सशक्त क्यों नहीं किया जा रहा है या वे कम सशक्त क्यों हो रहे हैं, इसके लिए आत्मनिरीक्षण और जवाब तलाशने की आवश्यकता है। लोगों में क्रोध है और वह बाहर नहीं निकल रहा है। उन्होंने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों ने राजनीति को छोड़ दिया है। यह राजनीति राजनीतिक दलों के बारे में नहीं है। सभी कार्यक्रम राजनीतिक हैं। जब नागरिक के अधिकारों के बारे में बात की जाती है, तो यह एक राजनीतिक मामला है। खाद्य सुरक्षा के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई जारी है और इसके बारे में लेख लिखे जा रहे हैं। यदि एक समूह केवल खाद्य सुरक्षा पर काम करता है और दूसरा पंचायती राज पर करता है, तो कोई भी आपसी जुड़ाव नहीं होगा। सभी ने अपनी 'दुकानें' लगा रखी हैं। सूचना के अधिकार पर बहस की गई है और काफी चर्चा की गई है और अब यह मंद पड़ गयी है। कुछ लोग हैं जो इसके बारे में लिखते हैं और बोलते हैं। हमारे बीच दो जातियां हैं। एक राष्ट्रीय स्तर पर है जहां निखिल डे, अरुणा रॉय और हर्ष मंदर जैसे लोग हैं, जिन्हें प्रो. शाह ने 'ब्राह्मण' कहा है - उनके तर्क (समाज के लिए उनकी चिंता) का रूपांतरण नहीं हो रहा है क्योंकि कार्यान्वयनकर्ता परियोजना मोड में काम करते हैं; इसे निश्चित वर्षों की एक निश्चित अवधि में समाप्त करना होगा और इसकी सूचना देनी होगी। प्रो. शाह ने प्रतिभागियों को चिंतन करने को कहा: 'क्या हम एक समूह के रूप में चर्चा करते हैं कि करुणा और अधिकारों के बीच का अंतर क्या है? जिन लोगों के लिए हम काम कर रहे हैं, उनके बारे में हमने कितनी महत्वपूर्ण चर्चा की है? 'उन्होंने कहा कि गैर-सरकारी संगठनों के बीच नागरिकता और नागरिक के अधिकारों के बीच विकसित समझ को उनके प्रस्तावों में रूपांतरित किया गया है। लेकिन यह उसके साथ शुरू होता है और उसके साथ ही समाप्त होता है। यह एक सामान्य प्रवृत्ति प्रतीत होती है, हालांकि अपवाद भी हैं। सशक्तिकरण से हमारा क्या मतलब है, इसे समझना और इसके विभिन्न पहलुओं को समझने पर स्पष्टता विकसित करने की आवश्यकता है। वक्ता ने राजनीतिक दलों से परे जाकर राजनीति (राजनीतिक दलों के मामले में राजनीति नहीं) के बारे में बात करने की आवश्यकता पर बल दिया। जब तक इस तरह के विचार-विमर्श नहीं होंगे, प्रोजेक्ट मोड में काम करने की प्रवृत्ति जारी रहेगी। निराशा की भाषा को कम करना और तर्कसंगत रूप से सोचना महत्वपूर्ण है, इसके लिए आत्मालोचना और स्पष्टता बहुत महत्वपूर्ण है।

■

सार्वजनिक सेवाओं तक टिकाऊ पहुंच बनाने के लिए समूहों को मजबूत करना

- सुकांत सरकार[1] और शैलेंद्र कुमार सिंह[2], PRADAN[3]

सुकांत ने प्रदान के दर्शन और काम के बारे में बताते हुए अपनी प्रस्तुति शुरू की। यह संगठन 1983 में स्थापित किया गया था और यह भारत के सात राज्यों में काम करता है, मुख्यतः मध्य और पूर्वी पठारी क्षेत्र में। इसकी पहुंच लगभग 6 लाख घरों में है। प्रदान एक निष्पक्ष और न्यायसंगत समाज की कल्पना करता है जहां हर किसी को गरिमा के साथ जीने का अधिकार है। इसका उद्देश्य गरीब लोगों के समूह की एजेंसी की भावना को प्रोत्साहित करना और बढ़ाना है ताकि वे सामूहिक रूप से सौदेबाजी कर सकें, समाज में बराबरी में अपनी जगह पा सकें और नागरिकता की जिम्मेदारी ले सकें।

प्रदान का विकास दर्शन यह है कि विकास किसी भी अन्य धारा की तरह ही एक जटिल प्रक्रिया है। इसलिए यह मानता है कि 'सबसे प्रतिभाशाली लोगों को सबसे गरीब लोगों के साथ काम करना चाहिए'। इसने हमदर्द और दीर्घकालिक प्रतिबद्धता वाले युवा योग्य लोगों को पहचानने, लैस करने और तैनात करने के लिए एक दृष्टिकोण का बीड़ा उठाया है, और उन्हें ग़रीब क्षेत्रों में बदलाव के लिए तकनीकी-प्रबंधकीय और सामाजिक-व्यवहार कौशल का सही मिश्रण प्रदान किया है। गरीबों का समूह बनाया जाता है और उनकी एजेंसियां उनके अधिकारों पर जोर देने के लिए विकसित की जाती हैं। दूसरा, प्रदान का मानना है कि 'परिवर्तन' की प्रक्रिया व्यक्ति और उसके माहौल के बीच परस्पर-क्रियाओं का एक कारक है। इसलिए 'स्वयं' और 'माहौल' का निर्माण करने के लिए कार्यक्रम तैयार किए गए हैं जो लोगों के लिए सुलभ और उपयुक्त हैं।

मुख्य केंद्रित क्षेत्र

- महिला-सामूहिक नेतृत्व वाली संस्कृति परिवर्तन प्रक्रियाओं को तेज करना: जब लोग संगठित होंगे, संवेदनशील बनेंगे और समाज में भेदभाव का एहसास करेंगे, तो वे संस्कृति परिवर्तन की प्रक्रियाओं का नेतृत्व करेंगे;
- पिछड़े परिवारों के लिए टिकाऊ आजीविका पैदा करना और उन्हें आय अनुकूलित करना;
- नागरिकों, खासकर महिलाओं के लिए के लिए स्थानीय प्रशासन और सेवा संस्थानों का पुनर्निर्माण;
- जमीनी स्तर पर माहौल को सक्षम बनाना, जहां गरीब जा सके और दावा कर सके, और
- विभिन्न स्तरों पर बहु-हितधारक भागीदारी का निर्माण। समूह समान सोच वाले नेटवर्क के साथ भागीदारी कर सकते हैं ताकि वे बड़े समाज को संयुक्त रूप से प्रभावित कर सकें।

स्वयं के निर्माण के लिए अपने कार्यों के माध्यम से, संगठन लोगों द्वारा गरीबी के कारणों को समझने के महत्व पर बल देता है; उन्हें लिंग, जाति और वर्ग के विभिन्न प्रकार के भेदभाव को समझने की जरूरत है जिससे कुछ समूह सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक हाशिए पर चले जाते हैं। लोगों को यह समझने में मदद करने के प्रयास किए जाते हैं कि गरीबी सिर्फ भौतिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि लोगों के भेदभाव और हाशिए पर होने के कारण है। शक्ति संरचनाओं, लिंग, हिंसा, समूह के रूप में काम करने

1. सुकांत सरकार 1995 से 'प्रदान' के साथ जुड़े है। कृषिविशेषज्ञ की शिक्षा प्राप्त करने वाले सुकांत समुदाय-उन्मुख परिवर्तन प्रक्रिया और प्रशासन में रुचि रखते हैं।
2. शैलेंद्र कुमार सिंह 2009 से 'प्रदान' के साथ जुड़े हैं। वे प्रशासन और लिंग आधारित समस्याओं को हल करने के लिए समुदाय उन्मुख प्रक्रिया में रूचि रखते हैं।
3. PRADAN - *Professional Assistance For Development Action*

और अन्य विकास विषयों पर प्रशिक्षण दिए जाते हैं। स्वास्थ्य, पोषण और आजीविका और उनके अंतर-संबंधों जैसे विभिन्न विषयों पर जीवन के नजरिए से चर्चा की जाती है, क्योंकि ये लोगों पर निरंतर प्रभाव डालते रहते हैं। स्वयं के स्तर पर इन प्रक्रियाओं से लोगों के बीच में बदलाव की आकांक्षाएं पैदा हुई हैं और उन्हें एकजुट होने और अपनी समस्याओं को संयुक्त रूप से हल करने की आवश्यकता महसूस हुई है।

समूहों का गठन

प्रदान ने महिलाओं के साथ सीधे काम करने के लिए एक सचेत रुख अपनाया है जो समाज के सबसे वंचित वर्ग हैं। जमीनी स्तर पर, महिलाएं स्व-सहायता समूह (एसएचजी) बना रही हैं। महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए और फिर टिकाऊ सेवाओं को सुनिश्चित करने के लिए समुदाय आधारित सेवा तंत्र बनाने के लिए महिला एसएचजी को ग्राम संगठनों (वीओ) में और फिर महासंघों में संघटित किया जाता है। ब्लॉक स्तर महासंघों का गठन इसलिए किया गया क्योंकि अकेले वीओ बड़े मुद्दों और बड़ी चुनौतियों का समाधान करने में असमर्थ रहे हैं। समूह मुद्दों की चर्चा और निगरानी करते हैं।

सामूहिकता को मजबूत बनाना और सशक्त बनाना

समूहों के गठन की प्रक्रिया शुरू होने के बाद प्रभावी ढंग से कार्य करने की उनकी क्षमता का निर्माण करना जरूरी हो जाता है। समूहों के संस्थागत विकास में सात क्षेत्र शामिल हैं, यानि, i. दृष्टि, ii. प्रशासन संरचनाएं, iii. सदस्यता संरचना, iv. संचालन के लिए संरचना, v. संपर्क निर्माण, vi. मूल्य और vii. आय / टिकाऊ मॉडल। उद्देश्य, दृष्टि और लक्ष्य की अभिव्यक्ति आवश्यक है।

व्यक्ति (महिला), परिवार और गांव स्तर पर 'जीवन की गुणवत्ता' की समझ और वांछित बदलाव आयामों को समझाने के लिए दूरदृष्टि अभ्यास किया जाता है। दूरदृष्टि को क्रियान्वित करने वाले बिंदुओं में परिवर्तित करने के लिए उसका रहस्योद्घाटन किया जाता है।

मूलभूत मूल्यों को ध्यान में रखा जाता है जैसे 'सहयोगिता का सिद्धांत' (जो निर्णय विकेन्द्रीकृत स्तर पर लिए जा सकते हों, उन्हें उच्च स्तर की संस्था द्वारा नहीं लिया जाना चाहिए), 'सर्वोच्चता का सिद्धांत' (महासंघों को प्रमुखता नहीं लेनी चाहिए, निर्णय लेने के लिए प्राथमिक सदस्यों की रुचि को ध्यान में रखा जाना चाहिए); और 'सेवक नेतृत्व' (हुक्म चलाने वाले नेताओं के परंपरागत तरीके के बजाय लोगों की सेवा करने वाले नेता)। सबके द्वारा सहमत नियम और कानून, सदस्यता के अधिकार और कर्तव्यों को शामिल किया जाता है। निर्णय लेने वाली शैली, संचार प्रक्रिया, पारदर्शिता और वितरण नेतृत्व सहित शासन संरचना पर भी चर्चा की जाती है।

समूहों को यह समझाने में मदद की गई है कि 'हम बाहर क्या देखना चाहते हैं' और 'यह सामूहिक रूप में कैसे दिखाया गया है'। विभिन्न प्रक्रियाओं और अभ्यासों के माध्यम से, सामूहिक व्यक्तियों को इनके महत्व का एहसास करने में मदद की जाती है: नेताओं की जवाबदेही, सदस्यता और सदस्यों की गुणवत्ता को परिभाषित करना, सदस्यों के अधिकार और कर्तव्यों और विभिन्न संस्थाओं/नेटवर्क के साथ संबंध स्थापित करना जो जिनके लक्ष्य समान हैं। संस्था के रूप में कार्य करने के लिए समूहों को सक्षम बनाने के लिए उन पर काफी ध्यान दिया गया है।

प्रशासन को प्रभावित करने के लिए कार्य

जब समूह परिवर्तन शुरू करने के लिए तैयार हों, तो उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए कार्यक्रमों को तैयार करने के बारे में सोचा जा सकता है। यूरोपीय संघ के प्रोजेक्ट के एक भाग के रूप में, स्थानीय शासन को प्रभावित करने के लिए समूहों की मदद करने पर मुख्य ध्यान केन्द्रित किया जाता है। जब तक व्यवस्था में परिवर्तन न हो, केवल योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से समुदायों को टिकाए रखने में मदद नहीं मिल सकती। नागरिकों को प्रशासन पर असर डालने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सात 'रणनीतिक हस्तक्षेप बाल्टी' विशिष्ट उद्देश्यों के साथ पहचाने गए हैं। प्रत्येक बाल्टी (बकेट) में गतिविधियां इस प्रकार हैं:

(i) नागरिक साक्षरता: नागरिक कर्तव्यों और अधिकारों पर शिक्षा और जागरूकता, सदैव तत्पर सुविधा प्रदाताओं के एक कैडर का निर्माण और सामाजिक सुरक्षा और अधिकारों पर पुस्तिकाएं तैयार करना। यह महत्वपूर्ण है कि लोग समझें और मानें कि उनके पास नागरिकों के रूप में अधिकार हैं और सरकार उन्हें खैरात नहीं, बल्कि उनके अधिकार दे रही है।

(ii) महिलाओं और उनके समूह की भागीदारी में सुधार: एसएचजी के व्यवस्थित प्रशिक्षण, ग्राम सभाओं और ग्राम पंचायतों में महिलाओं की भागीदारी और लिंग के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना।

(iii) अधिकारों और हकों को प्राप्त करने के लिए सामुदायिक आधारित संगठनों (सीबीओ) और पंचायती राज संस्थानों

(पीआरआई) के बीच सहयोगः पीआरआई-सीबीओ प्रशंसा कार्यशालाएं, मुद्दों और सेवाओं को हल करना और ग्राम पंचायत स्वयंसेवकों के लिए पुस्तिकाएं।

(iv) पीआरआई को सुदृढ़ बनानाः ग्राम पंचायतों (जीपी) के लिए संगठनात्मक विकास, कार्यान्वयन के लिए प्रक्रियाओं का मानचित्रण, व्यक्ति शक्ति, बुनियादी ढांचा, सिस्टम, संबंधता, अनुभव, दूरदृष्टि और कार्य योजना और साथ देना। झारखंड में, यह पहलू विशेष महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि पीआरआई आरंभिक चरण में हैं; मांगों को पूरा करने के लिए, आपूर्ति पक्ष की क्षमता को मजबूत किया जाना चाहिए।

(v) ग्राम पंचायतों के माध्यम से ढांचागत कार्यक्रम प्रदान करनाः आपूर्ति और मांग पक्ष के अंतर का आकलन करना, योजना तैयार करने में जीपी की सहायता करना, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीएस), जल एवं स्वच्छता (वाटसैन), शिक्षा और स्वास्थ्य कार्यक्रमों में साथ देना। पीआरआई द्वारा प्रदान करने में विश्वास काफी कम है और यह महत्वपूर्ण है कि वे अपनी क्षमता का प्रदर्शन कर सकें। यह कुछ अच्छी ढांचागत विकास परियोजनाओं के माध्यम से किया जा सकता है।

(vi) ग्राम पंचायत में सूचना केन्द्र और सहायता डेस्क बनानाः संसाधन और सूचना केंद्रों के रूप में जीपी, शिकायत और प्रक्रिया समर्थन, प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) के प्रमुख कार्यालय और सक्रिय प्रकटीकरण (पीएडी)।

(vii) समूहों द्वारा प्रशासन स्थिति की निगरानीः नागरिक रिपोर्ट, सामाजिक ऑडिट, एसएचजी गठबंधन, निर्वाचित प्रतिनिधियों के गठबंधन, नेटवर्क और अभियानों में जुड़ाव।

स्थानीय प्रशासन को प्रभावित करने के लिए उपरोक्त सभी पहलुओं को एक साथ हल किया जाना चाहिए। वक्ता ने कुछ तरीके बताए हैं जिसमें बकेट (बाल्टी) के तहत कुछ गतिविधियां की जाती हैं। जागरूकता पैदा करने के लिए रैलियों का आयोजन किया जाता है; चित्रमय छवियों की सहायता से सूचना प्रसार किया जाता है, घर-घर जाते हैं और इन प्रक्रियाओं के दौरान, विभिन्न हितधारकों की भूमिकाओं पर चर्चा की जाती है। चूंकि समूहों द्वारा मुद्दों को पहचानते रहते हैं और जब भी वे विशिष्ट कार्यवाही करने की योजना बनाते हैं, उन्हें इन कार्यों को आरंभ करने और प्रक्रिया को एक तार्किक अंत तक ले जाने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है। वीओ की सहायता जानकारी देकर की जाती है; शिक्षा का अधिकार (आरटीई), नागरिक साक्षरता और वाटसैन जैसे विशिष्ट पहलुओं पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (टीओटी) आयोजित किया जाता है। साथ ही, गांव के स्तर पर कई अनिवार्य समितियां जैसे स्कूल मैनेजमेंट कमेटी (एसएमसी) और ग्राम स्वास्थ्य, स्वच्छता और पोषण समिति (वीएचएसएनसी) भी प्रशिक्षित और समझने में मदद करती है कि उन्हें वीओ के साथ इंटरफेस क्यों करना चाहिए।

वीओ ने प्रगति और चिंतन के अपने स्वरूपों को बनाना शुरू कर दिया है। वे योजना बनाते हैं और तय करते हैं कि वे कैसे निगरानी करेंगे, इस बारे में चर्चा करते हैं कि कितने लोगों को योजनाओं का लाभ मिला है, किस मुद्दे को हल किया जाना है और क्या कार्यवाही करने की आवश्यकता है। प्रासंगिक सरकारी संकल्पों (जीआर) का एक भंडार वीओ के लिए विकसित किया गया है और उसे लगातार अद्यतन किया जाएगा। नागरिक अपने क्षेत्रों में प्रगति, मुद्दों और अंतराल पर रिपोर्ट तैयार करते हैं और इसे प्रशासन और पीआरआई के साथ साझा करते हैं; वे नीतियों के प्रभाव पर भी चर्चा करते हैं और सरकारी अधिकारियों के साथ आलोचना और प्रतिक्रिया साझा करते हैं। प्रशासन के साथ चल रही वार्ता के लिए राज्य स्तर पर एक गठबंधन भी बनाया गया है।

पीआरआई को मजबूत करने के अपने प्रयास में, 25 पंचायतों में एक पायलट कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी। पहली बार, पंचायतों और प्रदान के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। इसने जीपी को यह महसूस करने में मदद की है कि वे अलग-अलग संस्थाएं हैं जो निर्णय ले सकती हैं और अपने क्षेत्रों के विकास के लिए काम कर सकती हैं और वे केवल प्रशासन की शाखा मात्र नहीं हैं। नागरिकों को पीआरआई के प्रति अपनी जिम्मेदारी और ग्राम सभा में उनकी भागीदारी का महत्व समझने में सहायता की जा रही है। ग्राम पंचायत में विभिन्न हितधारकों के रिक्त स्थानों पर एक बड़े विचार-विमर्श की शुरुआत की गई है। जो सत्ता और अधिकार का आनंद ले रहे हैं वे खतरा महसूस कर रहे हैं, लेकिन समूह बहुत मजबूत हैं और ऐसी चुनौतियों का सामना करने में सक्षम हैं। 130 वीओ के प्रतिनिधियों ने जीपी चुनाव लड़े और चुने गए और विरोध का सामना कर रहे हैं। वीओ भी पीआरआई, ब्लॉक अधिकारी, जिला कलेक्टर (डीसी) और झारखंड के राज्यपाल सहित कई हितधारकों को प्रभावित करने के प्रयास कर रहे हैं। जिन सेवा प्रदाताओं ने अच्छा प्रदर्शन किया है उन्हें वे सम्मानित कर रहे हैं।

प्रभाव

इन सभी कार्यक्रमों और प्रक्रियाओं के कारण व्यवस्थागत परिवर्तन हुए हैं। जेंडर और बालिका शिक्षा के बारे में नए मानदंडों, हिंसा मुक्त गांवों, अंतर-जाति विवाह और कई अन्य मुद्दों पर नियमित चर्चा होती है। एसएमसी, माता समिति, ग्राम जल और स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) और वीएचएसएनसी जैसी सरकारी समितियों के साथ नियमित रूप से बातचीत होती है और सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी की जाती है। ये संघ विभिन्न विकास मंचों (स्वास्थ्य, शिक्षा, वाटसैन) के सदस्य बन गए हैं। समूह के सदस्यों को ग्राम पंचायत निष्पादन समिति (जीपीईसी) की बैठकों में नियमित रूप से आमंत्रित किया जा रहा है। एक नियमित ग्राम सभा है जो ग्राम मुद्दों पर व्यवस्थित निगरानी रखती है, ग्राम पंचायत कार्यालय खुले रहते हैं और समुदाय के मुद्दों को हल करने में सक्रियता दिखाई जाती है। संबंधित विभाग के कार्यों की निगरानी जीपी स्तर पर की जाती है। प्रज्ञा केंद्रों की सेवाओं में सुधार हुआ है और सूचनाएं सक्रिय रूप से सामने आई हैं। वित्तीय समावेशन, ऑनलाइन टिकट और वित्तीय उत्पाद, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, निवासी प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र और जन्म प्रमाणपत्र जैसी विभिन्न सेवाएं प्रदान करने की जनता की मांग के जवाब में सरकार द्वारा प्रज्ञा केंद्रों की शुरूआत की गई है। इससे पहले, वे पंचायत कार्यालय से बहुत दूर स्थित थे, हालांकि वे जीपी के साथ मिलकर काम करते हैं। हाल के प्रयासों के परिणामस्वरूप, उन्हें पंचायत परिसर में स्थानांतरित किया गया है।

जागरूकता बढ़ने पर स्थिरता हल हो जाती है, परिवर्तन की इच्छा देखी जा रही है और जिम्मेदारी लोगों को स्थानांतरित कर दी जाती है। सामुदायिक समूहों की व्यवस्था और प्रक्रियाओं के साथ-साथ आधारभूत नींव, समुदाय को नियमित आधार पर भरोसा करने का अवसर प्रदान करता है। समुदाय को 'समूह' के रूप में संगठित करके, ज्ञान के साथ सशक्त करके, परियोजना पूरी होने के बाद भी व्यवस्थित तरीके से मुद्दों को हल करने में सक्षम बनाता है। बाहरी हितधारकों का आयोजन एक वांछित दिशा में ऊर्जा लाता है। बाहरी हितधारकों के लिए, इसे करना आसान हो जाता है क्योंकि एक सामुदायिक संस्था एक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करती है।

प्रदान टीम ने इस रास्ते में कुछ चुनौतियों का सामना किया है। समुदाय में 'जीवन' परिप्रेक्ष्य से एक एजेंडा की स्थापना में समय लगता है। जमीनी स्तर पर आपूर्ति वाले संस्थानों के पास वितरित करने के लिए पर्याप्त क्षमता नहीं है। प्रशासन के ऊपर से-नीचे वाले दृष्टिकोण अक्सर लोकतांत्रिक प्रक्रियाओं को बाधित करते हैं। अपर्याप्त बजट आवंटन सेवा के प्रावधान की गुणवत्ता को प्रभावित करता है और बुनियादी ढांचे की अनुपलब्धता ग्रामीण व्यवस्था में जानकारी तक पहुंच को रोकती है।

प्रस्तुति के प्रमुख बिंदु

1. 'परिवर्तन' की प्रक्रिया व्यक्ति और उसके माहौल के बीच पारस्परिकता का एक कारक है। कार्यक्रम 'स्व' और 'माहौल' बनाने के लिए तैयार किए जाते हैं।
2. गरीबी भौतिक संसाधनों की कमी के कारण नहीं है, बल्कि लोगों के भेदभाव और हाशिए पर होने के कारण है।
3. स्वयं के स्तर पर शुरू की गई प्रक्रियाओं ने परिवर्तन की आकांक्षाओं को प्रेरित किया है और इससे लोगों में समूह बनाने और संयुक्त रूप से अपनी समस्याओं का समाधान करने की आवश्यकता को महसूस किया है।
4. स्थानीय शासन को प्रभावित करने के लिए समूहों की सहायता करने पर मुख्य ध्यान केंद्रित किया जाता है। जब तक व्यवस्था में परिवर्तन न हो, तब तक केवल योजनाओं का लाभ प्राप्त करने से समुदायों को बनाए रखने में मदद नहीं मिल सकती।
5. चूंकि समूहों द्वारा मुद्दों की लगातार पहचान करना जारी रहता है और वे विशिष्ट कार्यवाही करने की योजना बनाते हैं, इसलिए उन्हें इन कार्यों को आरंभ करने और प्रक्रिया को तार्किक अंत तक ले जाने के लिए समर्थन की आवश्यकता होती है।
6. जागरूकता बढ़ने के बाद स्थिरता हल हो जाती है, परिवर्तन की इच्छा देखी जा रही है और जिम्मेदारी लोगों को स्थानांतरित कर दी जाती है।
7. सामुदायिक समूहों की व्यवस्था और प्रक्रियाओं के साथ-साथ आधारभूत नींव, समुदाय को नियमित आधार पर भरोसा करने का अवसर प्रदान करता है।
8. समुदाय को 'समूह' के रूप में संगठित करके, ज्ञान के साथ सशक्त करके, परियोजना पूरी होने के बाद भी व्यवस्थित तरीके से मुद्दों को हल करने में सक्षम बनाता है। बाहरी हितधारकों के लिए, इसे करना आसान हो जाता है क्योंकि एक सामुदायिक संस्था एक इंटरफ़ेस के रूप में कार्य करती है।

■

'सेवा' शक्ति केंद्र (एसएसके) के अनुभव

- केतकी फ़णसे[4], रोशन पठान[5] और वर्षा ठाकुर[6]

संदर्भ

स्वाश्रयी महिला संघ (सेवा) चार दशकों से महिला अनौपचारिक श्रमिकों के साथ मिलकर उनके अधिकारों के लिए उनके संघर्ष में काम कर रहा है। इसकी सबसे हाल की पहल संगठन के कई सालों से सशक्तिकरण के एक तरीके के पुनरुद्धार पर केंद्रित है। सेवा गुजरात टीम में सेवा सामाजिक सुरक्षा ने सेवा दिल्ली और मध्य प्रदेश द्वारा स्थापित सेवा शक्ति केंद्र (एसएसके) के रूप में ज्ञात कार्यकर्ता सुविधा केन्द्रों का अनुकूलन करने का निर्णय लिया है, जिसमें फिर से अत्यधिक जोर अनौपचारिक महिला श्रमिकों को सरकारी सामाजिक सुरक्षा, स्वास्थ्य और पोषण कार्यक्रमों से जोड़ने पर है जिनकी वे हकदार हैं। वर्ष 2015 से गुजरात में सामाजिक सुरक्षा टीम द्वारा शुरू किए गए एसएसके ने स्वास्थ्य और सामाजिक सुरक्षा तक पहुंच के आसपास कई महत्वपूर्ण नवाचार लागू किए हैं। गुजरात के ग्रामीण और शहरी इलाकों में कुल 18 एसएसके हैं। एसएसके महिलाओं और युवाओं को सशक्त बनाना चाहते हैं।

स्वास्थ्य और बाल देखभाल जैसी सामाजिक सुरक्षा और सामाजिक सेवाओं पर ध्यान केंद्रित करना महत्वपूर्ण है। अनौपचारिक रोजगार को अक्सर कम और असुरक्षित आय, काम करने की खराब स्थिति और खतरे का जोखिम अधिक होता है। सामाजिक और श्रम सुरक्षा, जो आम तौर पर औपचारिक श्रमिकों को जोखिम प्रबंधन करने में मदद करते हैं, आमतौर पर इन श्रमिकों को शामिल नहीं करते हैं। इसके अलावा, भारत में, स्वास्थ्य सेवा प्रावधान के लिए खर्च सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का दो प्रतिशत से भी कम है।

सरकार ने एकीकृत बाल विकास योजना (आईसीडीएस), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई) स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम, और खाद्य सहायता कार्यक्रम जैसी कुछ सामाजिक योजनाओं को लागू किया है, जिससे सेवा के कई ग़रीब अनौपचारिक श्रमिकों को तत्काल और ठोस लाभ मिल सके। फिर भी कर्मचारियों को अत्यधिक नौकरशाही वाली योजनाओं तक पहुंचने में कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, भले ही वे उनके अस्तित्व के बारे में जानते हों।

'एसएसके' की भूमिका

एसएसके सेवा के संचालन के तरीके में बदलाव को दर्शाते हैं। इससे पहले, सेवा के सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी स्वास्थ्य सूचना और शिक्षा देने के लिए घर-घर गए थे। अब, इसके अतिरिक्त, वे एक केंद्रीय स्थान से भी कार्य करते हैं जहां अनौपचारिक श्रमिकों द्वारा अपने सुविधाजनक समय के दौरान उनसे संपर्क किया जा सकता है। जिन महिला अनौपचारिक श्रमिकों को समुदाय स्वास्थ्य कर्मचारी या स्वयंसेवकों के रूप में चुना जाता है, उन्हें उनके समुदाय से लिया जाता है और उनका चयन उनके नेतृत्व कौशल और समुदाय के

4. केतकी फणसे 'सेवा' के स्वास्थ्य विभाग में निगरानी और मूल्यांकन समन्वयक के रूप में कार्य करती है। वे समुदाय में एकत्रित किए गए डेटा का विश्लेषण करती हैं। इसके अलावा वे दस्तावेज़ के काम से जुड़े हुए हैं और रिपोर्ट तैयार करने में फील्ड स्टाफ को सहायता प्रदान करते हैं।
5. रोशन पठान पिछले 32 सालों से 'सेवा' में काम कर रहे हैं। वर्तमान में वह अहमदाबाद जिले के चार तालुकों के एक टीम नेता हैं। इसके साथ ही वह लोक स्वास्थ्य सेवा ट्रस्ट (एलएसएसटी) और लोक स्वास्थ्य मंडली (एलएसएम), सेवा स्वास्थ्य सहकारी समिति के सक्रिय बोर्ड सदस्य है।
6. वर्षा ठाकुर एक समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता और 'सेवा' के स्वास्थ्य विभाग में कार्यकर हैं। वह 'सेवा' की नेशनल ईन्श्योरन्स को-ओपरेटिव के बोर्ड सदस्य भी हैं।

साथ उनकी भागीदारी के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार, 'सेवा' की सदस्यता आधार की भागीदारी एसएसके के डिजाइन में बनाई गई है।

एसएसके के पहले के मॉडलों में, समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता ज्यादातर केंद्रों के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देते थे। अब, वे वास्तव में स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुरक्षा अधिकारों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में समुदाय के सदस्यों के साथ रहते हैं। वे जानकारी प्रदान करते हैं, फ़ॉर्म भरने में सहायता करते हैं और दस्तावेज़ीकरण तैयार करने में सहायता करते हैं। जब फॉर्म जमा करने होते हैं या जब समुदाय के सदस्यों को स्वास्थ्य सेवाओं का उपयोग करना होता है, तो सामुदायिक स्वास्थ्य कर्मचारी उनके साथ होते हैं ताकि वे किसी भी परेशानी या परेशानियों से निपट सकें।

'एसएसके' की क्षमता निर्माण

नए एसएसके को पुनः शुरू करते समय, सेवा ने सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के शिक्षा और सशक्तिकरण पर ध्यान केंद्रित किया है, क्योंकि वे समुदाय और सरकार के बीच के पुल का काम करते हैं। समुदाय के सदस्यों व्यवस्था के माध्यम से प्रभावी ढंग से गुजरने के लिए, चयनित नेताओं को सामाजिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा के प्रावधान में शामिल विभिन्न सरकारी विभागों के बारे में जानने की जरूरत थी। उन्होंने यह भी सीखा कि कौनसा विभाग किसके लिए जिम्मेदार है, कौनसे फॉर्म और दस्तावेज आवश्यक हैं, और अलग-अलग विभाग में किस उद्देश्य के लिए किससे संपर्क किया जाना चाहिए।

प्रशिक्षण के चरण में, स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के साथ उनके पर्यवेक्षक सरकारी विभागों में जाते थे ताकि वे काम करके सीख सकें और अधिकारियों के साथ बातचीत करने के लिए तैयार हो सकें। यह ऐसा कुछ नहीं था, जो कई महिलाओं के लिए आसानी से हो गया हो। जिनके लिए अपने समुदायों के साथ बातचीत करने में सहज रहता था, उन्हीं के लिए राज्य के अधिकारियों के साथ बातचीत करना मुश्किल हो जाता था। सेवा स्वास्थ्यकर्मियों ने सरकारी अधिकारियों के साथ लगभग लगातार संपर्क को बनाए रखने की कोशिश की ताकि समस्याओं और प्रगति पर रिपोर्ट करके और संयुक्त गतिविधियों के चलने के बाद उनके रिश्तों को मजबूत किया जा सके। अधिकारियों को सामुदायिक स्तर पर आयोजित जागरूकता अभियानों (प्रदर्शनियों, वीडियो क्लिप, पुस्तिकाओं का वितरण, आदि सहित) के तहत के विभिन्न सरकारी कार्यक्रमों के बारे में बताने के लिए और समुदाय के सदस्यों के साथ सीधे संवाद में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है।

'एसएसके' के साथ सेवा टीम के सदस्यों के अनुभव

प्रस्तुतकर्ताओं में से एक, रोशन पठान, 32 साल से अहमदाबाद जिले में सेवा के स्वास्थ्य संबंधी कार्य में एक दल के नेता के रूप में काम कर रही हैं। एसएसके के साथ अपनी यात्रा साझा करते हुए, वक्ता ने उल्लेख किया कि जब सेवा ने एसएसके के माध्यम से सरकारी योजनाओं के बारे में जानकारी देने का फैसला किया, तो स्वास्थ्य टीम ने विभिन्न योजनाओं को लागू करने के लिए जिम्मेदार विभागों का दौरा किया और इन योजनाओं के लाभों के लाभ लेने के विभिन्न पहलुओं पर जानकारी एकत्र की। एक सर्वेक्षण किया गया कि एसएसके के प्रभाव क्षेत्रों में लोगों की जानकारी की जरूरतों का आकलन कैसे किया जाता है और उन्हें कैसे प्राप्त किया जा सकता है। क्षेत्रवार बैठकें आयोजित की गई। टीम ने सहायता प्राप्त करने के लिए सरपंच, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता (एडब्ल्यूडब्ल्यूएस), मान्यता प्राप्त सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता (आशा) कार्यकर्ता और स्थानीय नेताओं से मुलाकात की। स्थानीय लोगों से मिलने के लिए सरकारी अधिकारियों को भी आमंत्रित किया गया था। 'जनसंवाद' के द्वारा लोगों ने उनकी जरूरतों पर चर्चा की और योजनाओं के कार्यान्वयन और उनके क्षेत्र में सेवाओं के कामकाज से संबंधित उनकी चिंताओं को उठाया। इसमें समय लगा, लेकिन धीरे-धीरे सेवा प्रदाताओं और सरकारी कर्मचारियों ने इन संवादों में भाग लेना शुरू किया और स्थानीय समुदाय के लिए उनका समर्थन प्रदान किया।

लोगों तक पहुंचने के लिए स्थानीय नेतृत्व का निर्माण करना महत्वपूर्ण था। स्थानीय युवाओं की पहचान की गई और विभिन्न विभागों और संबंधित अधिकारियों के साथ संबंध स्थापित करने में मदद की। यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नेताओं को पहचानने और प्रशिक्षित करने का एक सचेत निर्णय था कि लोगों को हकदारी की मांग करने की प्रक्रिया को बनाए रखने में सक्षम हों, भले ही सेवा इन क्षेत्रों से हट जाए। एसएसके के माध्यम से लोगों को जानकारी प्राप्त करने के लिए न केवल सहायता प्रदान की जाती है, बल्कि आवेदन भरने के लिए, उन्हें विभाग में जमा करने और लाभ प्राप्त होने तक उनका पालन करने के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है।

एक और प्रस्तुतकर्ता, वर्षा ने बताया कि एसएसके के साथ काम करना शुरू करने से पहले, वह सेवा में एक समुदाय आधारित स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में लगी हुई थी। शुरू में, उसके लिए कार्यालय में बैठना मुश्किल था, क्योंकि वह क्षेत्र में काम करती थी। इसके अलावा, उनकी जाति में पारंपरिक रिवाज के अनुसार, महिलाओं को घूंघट निकालना होता था। इस नई भूमिका में इस प्रथा को निभाना कठिन था। अपने वर्तमान कार्य में, वह लोगों के साथ विभिन्न योजनाओं के लिए आवेदन पत्र साझा करती है और उन सभी दस्तावेजों के बारे में बताती है जो लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक होंगे। वे सभी दस्तावेज लाए जाने के बाद, वह आवेदन फॉर्म भरने में उनकी मदद करती है और तब तक सहायता प्रदान करती है जब तक उन्हें लाभ प्राप्त नहीं हो जाता। धीरे-धीरे, उसे अपने समुदाय की स्वीकृति प्राप्त हुई और जिन लोगों को वह सहयोग प्रदान कर रही थी उनसे भी आभार स्वीकृति प्राप्त हुई।

'सेवा' में शामिल होने से पहले, वर्षा अपने घर तक ही सीमित थी और शायद ही कभी अकेले बाहर निकली थी। यहां तक कि अगर वह अपने मां के घर भी जाना चाहती थी, तो उसे बस टिकट के लिए अपने पति पर निर्भर होना पड़ता था। आज, वह गुजरात में ही नहीं, बल्कि राज्य के बाहर अकेले यात्रा करने में आत्मविश्वास महसूस करती है। उसने 'सेवा' द्वारा आयोजित दस दिनों की यात्रा पर थाईलैंड का दौरा भी किया है। एसएसके के साथ अपनी यात्रा में, उन्होंने न केवल आवेदनों को भरना सीखा है, बल्कि यह भी कि संबंधित अधिकारियों से कैसे बातचीत की जाती है और ब्लॉक और जिला अधिकारियों का समर्थन हासिल करने के लिए उनके साथ संबंध कैसे बनाए जाते हैं।

'एसएसके' टीम के लिए चुनौती

सरकारी विभागों के अधिकारियों को अक्सर स्थानांतरित किया जाता है और उन्हें नए पदाधिकारियों के साथ फिर से संबंध बनाने होते हैं ताकि समुदाय के हक प्राप्त करने के लिए उनका समर्थन प्राप्त हो सके।

समुदाय के लिए 'एसएसके' के लाभ

वक्ताओं ने बताया कि एसएसके सेवा के सदस्यों के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध हुआ है। इससे पहले, उन्हें सरकारी योजनाओं के लाभ पाने के लिए काफी लंबी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। वे अक्सर अधबीच में ही छोड़ देते थे क्योंकि वे प्रशासनिक बाधाओं से निपटने में सक्षम नहीं थे। अक्सर, वे अपनी पात्रता से वंचित रह जाते थे क्योंकि उनके पास आवेदन की प्रक्रिया का पालन करने के लिए पर्याप्त जानकारी या समर्थन नहीं था। महिलाओं को सबसे ज्यादा नुकसान होता है क्योंकि वे योजनाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए पुरुष अधिकारियों के पास आने में सहज या आत्मविश्वास महसूस नहीं करती हैं। अब एसएसके के समर्थन के बिना समुदाय के सदस्यों ने अपने आप विभागों से संपर्क करना शुरू कर दिया है। यह एसएसके टीम के लिए एक बहुत संतोषजनक प्रगति है।

केतकी ने एसएसके के पहले प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत कुछ प्रमुख बिंदुओं का अनुवाद किया और दोहराया।

प्रस्तुति के प्रमुख बिंदु

1. अनौपचारिक रोजगार को अक्सर कम और असुरक्षित आय वाला, काम करने की खराब स्थिति वाला और खतरे के अधिक जोखिम वाला माना जाता है। सामाजिक और श्रम सुरक्षा आमतौर पर इन श्रमिकों को शामिल नहीं करते हैं।
2. सामुदायिक स्वास्थ्य कार्यकर्ता सेवा के सदस्य हैं, जिन्हें एसएसके के लिए उनके नेतृत्व कौशल और समुदाय के साथ उनकी भागीदारी के आधार पर चुना जाता है। सेवा की सदस्यता का भागीदारी आधार एसएसके के डिजाइन में बनाया गया है।
3. समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ता स्वास्थ्य और अन्य सामाजिक सुरक्षा अधिकारों तक पहुंचने की पूरी प्रक्रिया में समुदाय के सदस्यों के साथ रहते हैं।
4. सेवा समुदाय स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के शिक्षा और सशक्तिकरण पर केंद्रित है, क्योंकि वे समुदाय और सरकार के बीच पुल हैं।
5. सेवा स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं ने सरकारी अधिकारियों के साथ समस्याएं और प्रगति पर रिपोर्ट करके और चलाने वाली किसी भी संयुक्त कार्यकलाप के बाद लगातार संपर्क जारी रखा है।
6. लोगों तक पहुंचने के लिए स्थानीय नेतृत्व का निर्माण करना महत्वपूर्ण है। यह सुनिश्चित करने के लिए स्थानीय नेताओं को पहचानने और प्रशिक्षित करने का एक सचेत निर्णय था कि लोगों को अधिकार मिलने की इस प्रक्रिया को बनाए रखा जा सके।

■

झारखंड में पारदर्शी और जवाबदेह शासन प्रणाली के लिए पहल

- सस्मिता जेना[7], 'वेल्थंगरहिल्फ'

सस्मिता जेना ने इस पर प्रकाश डाला कि कैसे 'वेलथंगरहिल्फ' द्वारा 2014 से झारखंड राज्य में कार्यान्वित हो रही 'गुड गवर्नेंस' परियोजना के एक भाग के रूप में समुदाय को जुटाने और समुदाय आधारित निगरानी के साथ जुड़ा हुआ है। 'वेलथंगरहिल्फ' दुनिया के कई हिस्सों और भारत में काम करता है। यह पिछले 45 वर्षों से काम कर रहा है।

'वेलथंगरहिल्फ' टीम इस समझ द्वारा निर्देशित है कि भ्रष्टाचार से लड़ने और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा देने से पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली स्थापित कर सकते हैं जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है। पारदर्शी व्यवस्था नागरिकों को प्रासंगिक और समय पर जानकारी साझा करके उनके अधिकारों का दावा करने के लिए उन्हें सक्षम बनाती है। ऐतिहासिक उपेक्षा, सबसे पिछड़े समूहों अर्थात आदिवासी और दलितों का लगातार बहिष्कार और गहरे जड़ें जमाए बैठे भ्रष्टाचार ने सार्वजनिक सेवा वितरण प्रणाली में लोगों के विश्वास को कम किया है। झारखंड राज्य इसका अपवाद नहीं है। अपने स्थानीय साझेदारों के साथ, 'वेलथंगरहिल्फ' झारखंड के बहुत कम विकसित जिलों (खुंटी, दुमका, पाकुर और साहेबगंज) में काम कर रहा है ताकि गरीबी और सामाजिक बहिष्कार को कम करने के लिए गुणवत्तायुक्त सार्वजनिक सेवाओं की प्राप्ति और वितरण में सुधार किया जा सके। यह पहल 78 पंचायतों और 950 गांवों में कार्यान्वित की जा रही है। यह कार्यक्रम मुख्य रूप से ग्रामीण रोजगार, स्वास्थ्य और पोषण और शिक्षा पर केंद्रित है। कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर सेवा देने और पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं की क्षमताओं को बढ़ाना है। इस पहल का लक्ष्य बेहतर नागरिक भागीदारी के लिए स्थानीय स्वशासन निकायों को सशक्त बनाने और सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर योजना, प्रबंधन और निगरानी रखना भी है। स्थानीय प्रशासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए समुदाय को जुटाना और भागीदारी महत्वपूर्ण हैं। इस पहल ने सार्वजनिक सेवाओं और सूचना प्रसार में महत्वपूर्ण अंतराल को दूर करने के लिए सभी प्रमुख कार्यकर्ताओं को शामिल करने के लिए बहु-हितधारक दृष्टिकोण अपनाया है।

इस परियोजना को अधिकार आधारित दृष्टिकोण का उपयोग करके और इस धारणा के साथ निष्पादित किया जा रहा है कि समुदाय को जुटाना एक अभिनव रूपरेखा के भीतर होना चाहिए ताकि इसे क्षेत्र में व्यवस्थित रूप से लागू किया जा सके और इच्छित परिणाम प्राप्त कर सकें। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि लोग निर्णय लेने की प्रक्रिया में भाग लें। जब तक ऐसा नहीं होता, जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और सेवा प्राप्तकर्ता और प्रदाताओं के बीच मौजूद अंतराल को दूर नहीं किया जा सकता है। इस पूरी प्रक्रिया की प्रकृति राजनीतिक है।

कार्यक्रम के प्रमुख क्षेत्र

1. सीबीओ की क्षमता निर्माण

लोगों को अधिकारों का उपयोग करने के लिए जानकारी की आवश्यकता होती है। लेकिन जब तक वे इस जानकारी को अपने जीवन में लागू करने और उनके लाभ के लिए उपयोग करने की आवश्यकता नहीं समझते हैं, तब तक जानकारी का कोई मतलब नहीं है। यही कारण है कि स्व-सहायता दृष्टिकोण पर बल दिया गया है जहां लोगों को जानकारी प्राप्त करने और अपने अधिकारों का उपयोग करने के लिए इसका उपयोग करने में सक्षम बनाया गया है। एसएमसी और

7. सस्मिता जेना पिछले 7 सालों से Welthungerhilfe से जुड़ी हुई है। विकास कार्यों के क्षेत्र में 17 से अधिक वर्षों का अनुभव है और आजीविका, शासन, मानवाधिकार और वकालत जैसे मुद्दों पर कार्य करती है।

वीएचएसएनसी जैसे संवैधानिक ढांचों को मजबूत करने पर ध्यान केंद्रित किया जाता है जिसमें संवैधानिक जनादेश होता है, निर्णय लेने में भाग लेने का दायरा और बदलाव करने की क्षमता होती है। उदाहरण के लिए, एसएमसी से स्कूल विकास योजनाओं को बनाने में भाग लेने की आशा की जाती है। इस प्रक्रिया में शामिल होने से, वे न केवल प्रति वर्ष बच्चों के नामांकन का बल्कि विद्यालय के लिए बुनियादी सुविधाओं और मानव संसाधन की आवश्यकता का भी आकलन करने में सक्षम होंगे। बजट आवंटन एसएमसी द्वारा विकसित और प्रस्तुत योजनाओं से जुड़ा हुआ है। गांव में शिक्षा सेवाओं को सुव्यवस्थित करने में अपनी क्षमता को स्वीकार करते हुए, सेवाओं की योजना, समीक्षा और निगरानी के लिए उनकी क्षमता को मजबूत किया गया है। नतीजतन, वे केवल सेवाओं की ही मांग नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह भी सुनिश्चित करने के लिए कि अपने आप कार्रवाई कर रहे हैं कि स्कूल ठीक से काम करें। एक उदाहरण में, एसएमसी ने स्कूल में बाड़ लगाने की मांग की थी, लेकिन धन जारी होने का इंतजार करने के बजाय, उन्होंने बाड़ लगाने के लिए समुदाय से योगदान प्राप्त कर लिया।

2. अति लघु (सूक्ष्म) योजना के लिए स्थानीय स्वयंसेवक समूह आधार बनाना

जब तक समुदाय योजना बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, तब तक योजनाओं को ऊपर से लंबित कर दिया जाएगा। सामुदायिक रेडियो स्वयंसेवकों, तत्पर संवाददाताओं या सूचना मित्रों के रूप में स्थानीय नेताओं को सार्वजनिक योजनाओं और कार्यक्रमों का संग्रह प्रदान किया गया है। प्रत्येक गांव में, एक पुरुष और एक महिला स्वयंसेवक होता है जिसे समुदाय को जानकारी प्रदान करने के लिए प्रशिक्षित किया जाता है। वे लोगों का विभिन्न पहलुओं पर मार्गदर्शन करते हैं जिनमें फॉर्म भरना और अपना आवेदन पत्र कहां जमा करना शामिल है। इस दृष्टिकोण ने गांव के स्तर पर क्षमता बनाए रखने और परियोजना पर समुदाय की निर्भरता को कम करने में मदद की है। कई क्षेत्रों में पहलुओं को एक पायलट आधार पर लागू किया जाता है, जो उपयोगी साबित होने पर, राज्य सरकार सहयोग के माध्यम से आगे बढ़ाए जाएंगे। सभी कार्यक्रमों में, महिलाओं की भागीदारी को महत्व दिया जाता है। महिलाएं बैठकों में भाग लेने, बोलने और सार्वजनिक रूप से उनके मुद्दों की आवाज उठाने लगी हैं। हालांकि, यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें पुरुषों और महिलाओं को समान स्तर तक लाने में अधिक समय लेगा।

3. समुदाय आधारित निगरानी

वीएचएसएनसी के उपयोग के लिए सचित्र मूल्यांकन टूल विकसित किए गए हैं। इसमें आशा, आक्ज़िलरी नर्स मिडवाइव्स (एएनएम) और एडब्ल्यूडब्ल्यूस द्वारा प्रदान की गई सेवाओं की एक सूची है। समिति के सदस्य हर महीने सेवाओं पर नज़र रखते हैं। इस प्रक्रिया से उन्हें जो हक प्राप्त नहीं हो रहे उनका पता चलता है और इसके लिए कारण जानने में मदद मिलती है। उदाहरण के लिए, वे देख सकते हैं कि आंगनवाडियों (एडब्ल्यूएस) या स्कूलों में उनके बच्चों को क्या खिलाया जा रहा है। इस विश्लेषण के आधार पर, वे संबंधित सेवा प्रदाता और / या अग्रिम कार्यकर्ताओं के साथ बातचीत करते हैं। इस साधन ने समुदाय को जुटाने के लिए अग्रिम कार्यकर्ताओं को भी सेवाएं प्रदान की हैं, सेवाओं की निगरानी और अंतर को अधिक प्रभावी ढंग से पहचानने के लिए सक्षम बनाया है। 200 गांवों में से 50 प्रतिशत में जहां यह काम किया गया है, समुदाय ने गांव स्वास्थ्य योजनाओं के विकास में भाग लेना शुरू कर दिया है। आम तौर पर इन योजनाओं को समुदाय की जरूरतों पर ध्यान दिए बिना और स्वास्थ्य से संबंधित वास्तविक जरूरतों और अन्य पहलुओं को अधिक ध्यान देने के बिना काफी सतही रूप से तैयार किया जाता है, जिन पर अधिक ध्यान देने की आवश्यकता होती है। हालांकि, अगले चरण (ब्लॉक और जिला स्तर) पर ग्राम स्तर की योजना अभी ठीक से प्रतिबिंबित नहीं हुई है और यह चिंता का क्षेत्र है।

4. सामाजिक ऑडिट

दुमका जिले के जाम ब्लॉक में सामाजिक ऑडिट की गई थी। इस परीक्षण को सुशासन परियोजना क्षेत्र में शुरू किया गया था और सफलतापूर्वक पूरा हो गया था। इसके बाद, यह अब सरकारी सोशल ऑडिट यूनिट (एसएयू), झारखंड द्वारा राज्य भर में किया जा रहा है। यह पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक अनिवार्य प्रक्रिया है और एक चुनौतीपूर्ण प्रक्रिया है।

5. राज्य और जिला स्तर के प्रशासन के सहयोग से अभिनव भागीदारी साधनों का विकास और उपयोग

मातृ और नवजात शिशु के स्वास्थ्य के मुद्दों पर सामुदायिक सहभागिता साधन (टूल), सहभागी लर्निंग एंड एक्शन (पीएलए) का उपयोग 100 गांवों में किया गया था। पीएलए को राज्य सरकार द्वारा पूरी तरह से स्वीकार किया गया और एक सर्वोत्तम अभ्यास मॉडल के रूप में अपनाया गया है। झारखंड सरकार ने अब इसे पूरे राज्य में लागू कर दिया है। इससे समुदाय, विशेष रूप से महिलाओं को बीमार स्वास्थ्य पद्धतियों को बदलने और सरकार से उनके अधिकारों की मांग करने में मदद मिली है।

5.1 पारस्परिक सीख और कार्यवाही: पिक्चर कार्डों का उपयोग करके माता और नवजात शिशुओं से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की

जाती है। महिलाओं को पहले माता और बाल स्वास्थ्य (एमसीएच) के विभिन्न पहलुओं, उपलब्ध सेवाओं और देखभाल और प्रथाओं में वांछित परिवर्तनों के बारे में सूचना प्राप्त होती है। इसके बाद वे अपने हक की मांग करती हैं। महिलाओं ने जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई) और ए.डब्ल्यू.एस. में सेवाओं के तहत लाभ मांगने के लिए जानकारी का इस्तेमाल किया है। यह साधन और दृष्टिकोण 100 जिलों में संचालित किया गया था और अब इसे झारखंड सरकार द्वारा अपनाया गया है। यह राज्य सरकार द्वारा आशा कार्यकर्ताओं के प्रशिक्षण मॉड्यूल के अध्याय 7 में शामिल किया गया है।

5.2 माताओं के लिए मोबाइल: यह एक मोबाइल एप्लिकेशन है जो सुरक्षित डिलीवरी तक गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य मानकों को रिकॉर्ड करने में आशा कार्यकर्ताओं की मदद करता है। इस पहल को सूचना और प्रौद्योगिकी विभाग और सामुदायिक एकीकरण सेल, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के सहयोग से कार्यान्वित किया जा रहा है।

5.3 माइक्रो प्लानिंग फ्लिप बुक: सामुदायिक स्तर पर लागू एक सहभागी योजना और शासन टूल है। यह सहकारी माइक्रो-योजनाओं को तैयार करने और लागू करने और सूचनाओं को बढ़ाने और सरकारी योजनाओं तक पहुंच बनाने में मदद करता है। इस तरह के टूल का गहन संवर्धन और अनुप्रयोग एमजीनरेगा के लिए महत्वपूर्ण बदलाव का साधन बन सकता है क्योंकि लोग न केवल इसके माध्यम से जानकारी प्राप्त करेंगे बल्कि यह प्रक्रियाओं पर भी असर डालेगा। इन अभिनव टूल्स ने समुदाय को एकजुट करने में और साथ ही सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया में तेजी लाने में मदद की है।

6. ग्रामीण विकास के लिए स्थानीय स्वशासन के नव-निर्वाचित प्रतिनिधियों को सक्षम बनाना

14वें वित्त आयोग के निर्णय के तहत, ग्राम पंचायत विकास योजना (जीपीडीपी) बनाने के लिए 2015-2020 के दौरान लगभग दो लाख करोड़ रुपये सीधे पीआरआई को हस्तांतरित किए जाने हैं। जब तक पंचायत इस पैसे का उचित उपयोग करने के लिए सक्षम नहीं हो जाती, तब तक धन के दुरुपयोग होने की काफी संभावना है। योजना बनाने और बजट और व्यय को ट्रैक करने के लिए पीआरआई प्रतिनिधियों को सक्षम बनाया जाता है। योजना बनाओ अभियान और जीपीडीपी योजना की प्रक्रिया के लिए एक फ्लिप बुक विकसित की गई है, जिसमें योजना प्रक्रिया के सभी चरणों को शामिल किया गया है, जैसे मुद्दे की पहचान, विश्लेषण, संसाधन और सामाजिक मानचित्रण आदि। यह योजना तैयार करने के लिए कदम दर कदम उठाने के लिए समुदाय को निर्देशित करने के लिए किया गया है और यह सुनिश्चित करने के लिए किया गया है कि महिलाओं, प्रवासियों आदि सहित सभी पिछड़े समूहों को योजना में शामिल किया जाए। टूल और मैनुअल विकसित किए गए हैं और स्थानीय स्तर पर क्षमताओं के निर्माण के लिए एक सोपानी मॉडल का उपयोग किया जाता है।

चुनौतियों का सामना

- गुणवत्ता नियंत्रण बनाए रखना
- आकार बढ़ाने के लिए अनुमति प्राप्त करना समय लेने वाला और श्रमसाध्य है
- सुनिश्चित करना कि सबसे अधिक बहिष्कृत समूहों को सभी चरणों में शामिल किया जाए
- प्रशिक्षित स्वयंसेवकों का हट जाना
- जिन लोगों के भ्रष्टाचार का खुलासा किया जाता है उनकी प्रतिकूल प्रतिक्रियाओं का सामना करना, विशेष रूप से सामाजिक ऑडिट की प्रक्रिया में

प्रस्तुति के प्रमुख बिंदु

1. भ्रष्टाचार से लड़ने और लोगों की भागीदारी को प्रोत्साहित करने से पारदर्शी और जवाबदेह प्रणाली स्थापित हो सकती है जो विकास के लिए महत्वपूर्ण है।
2. कार्यक्रम का उद्देश्य बेहतर सेवा प्रदान करने और पारदर्शिता और जवाबदेही बनाए रखने के लिए सार्वजनिक सेवा प्रदाताओं और कार्यकर्ताओं की क्षमता बढ़ाना है।
3. स्थानीय स्व-शासन प्रणाली को मजबूत करने के लिए समुदाय को जुटाना और भागीदारी करना महत्वपूर्ण हैं।
4. जब तक लोग भाग न लें, जवाबदेही सुनिश्चित नहीं की जा सकती है और सेवा प्राप्त करने वालों और प्रदाताओं के बीच मौजूद अंतराल को दूर नहीं किया जा सकता है।
5. स्व-सहायता दृष्टिकोण पर वहां बल दिया गया है, जहां लोग जानकारी प्राप्त करने और अपने अधिकारों को हासिल करने के लिए उपयोग करने में सक्षम हैं।
6. समुदाय संरचनाओं (ग्राम स्तरीय समितियों) को मजबूत करने पर फोकस है जिस पर एक संवैधानिक जनादेश है और निर्णय लेने में भाग लेने का दायरा और बदलाव लाने की क्षमता है।
7. जब तक समुदाय योजना बनाने की प्रक्रिया में भाग नहीं लेता, तब तक योजनाओं को शीर्ष द्वारा लंबित कर दिया जाएगा। ■

भारत के पांच पिछड़े जिलों में मांग पैदा करने के लिए डीपीओ को मज़बूत करना

- गौरब सेन[8], सम्मिलित विकास जानकारी, जर्मन लेप्रसी और टीबी रिलीफ एसोसिएशन

गौरब सेन ने बताया कि जर्मन लेप्रसी और टीबी रिलीफ एसोसिएशन (जीएलआरए) ने विकलांग लोगों के संगठनों (डीपीओ) को मजबूत करने के लिए 2014 से इस परियोजना को लागू किया है। सम्मिलित विकास जानकारी परियोजना का उद्देश्य चार राज्यों - उड़ीसा, बिहार, मध्य प्रदेश और गुजरात के पांच पिछड़े जिले में सार्वजनिक योजनाओं के बारे में जानकारी के लिए विकलांगों (पीडब्ल्यूडी) की पहुंच में सुधार लाना है।

परियोजना के मुख्य उद्देश्य हैंः ए) सार्वजनिक सेवाओं को प्रदान करने की गुणवत्ता में सुधार करना जिसके पीडब्लूडी हकदार हैं, बी) डीपीओ को समाज में अपनी भागीदारी बढ़ाने के लिए तैयार करना और सशक्त बनाना, सी) सेवा प्रदाताओं सहित प्रशासनिक प्रणालियों में जवाबदेही को बढ़ावा देना, डी) समान अवसर सुनिश्चित करना और पीडब्लूडी के लिए बेहतर जीवन गुणवत्ता प्रदान करना, और ई) गरीबी को कम करना और समावेशी विकास को बढ़ावा देना।

परियोजना को कार्यान्वित करने की प्रक्रिया में, जीएलआरए के साथी संगठनों ने घर-घर सर्वेक्षण करके पीडब्ल्यूडी की पहचान की है और उनके प्रोफाइल के साथ एक डेटाबेस तैयार किया है। पहचान के बाद, गांव और पंचायत स्तरों पर विकलांग लोगों के समूह (डीपीजी) का गठन किया गया। एक गांव / पंचायत में रहने वाले सभी पीडब्ल्यूडी समूहों को समूह के सदस्य के रूप में नामित किया गया था। गंभीर विकलांगता या मानसिक मंदता, मानसिक बीमारी और आत्मकेंद्रित (ऑटिज्म) व्यक्तियों के मामले में, उनके संरक्षक को डीपीजी के सदस्यों के रूप में शामिल किया गया था। ब्लॉक स्तर पर डीपीजी के नेता डीपीओ के सदस्य के रूप में नामांकित होते हैं। परियोजना क्षेत्र के कुल 48 ब्लॉकों में यह परियोजना लागू की जा रही है और प्रत्येक ब्लॉक में एक डीपीओ का गठन किया गया है। कुल 48 डीपीओ हैं जिनमें 1547 सदस्य हैं।

डीपीओ के सदस्यों को डीपीओ की संरचना, दृष्टि और मिशन पर जानकारी दी जाती है। डीपीओ सदस्यों को एक बाहरी परामर्शदाता, कम दृष्टि वाले व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षित किया गया है। सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए डीपीओ बिल्डिंग गाइड तैयार की गयी है। अपने मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सदस्य हर माह मिलते हैं। बैठकों में चर्चा किए गए कुछ पहलू इस प्रकार हैंः सरकारी योजनाएं और सेवाएं; योजना संबंधी सूचना और पाने के लिए सूचना के अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत आवेदन करने की प्रक्रिया, सरकार के साथ पैरवी। बैठकों के दौरान कार्यवृत्त तैयार किए जाते हैं और संकल्प मंजूर किए जाते हैं।

परियोजना के तीसरे वर्ष में, डीपीओ से चयनित नेताओं के साथ प्रत्येक जिले में विकलांग पीपुल्स फेडरेशन (डीपीएफ) का गठन शुरू हो गया है। वर्तमान में, परियोजना में पांच जिला स्तरीय डीपीएफ हैं।

डीपीओ को मजबूत करना

साथी संगठनों ने पहले दो वर्षों के दौरान डीपीओ को आवेदन पत्र

8. गौरब सेन 2014 से परियोजना प्रबंधक के रूप में जर्मन लेप्रसी एंड टीबी रिलिफ एसोसिएशन (भारत) साथे जुड़े हुए है। विकास क्षेत्र में उनके पास 14 साल का कार्य अनुभव है, जिसमें से वे 11 साल तक विकलांगता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं।

लिखने, आरटीआई आवेदन पत्र दाखिल करने और पैरवी कौशल विकसित करने के लिए प्रशिक्षण और तैयार करने के लिए सार्थक सहयोग प्रदान किया था।

विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से डीपीओ को मजबूत किया जाता है:

- हर साल, डीपीओ सदस्यों के लिए पुनश्चर्या प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है। इन दो दिवसीय प्रशिक्षण में, प्रतिभागियों को डीपीओ बनाने के लिए प्रक्रियाओं, पैरवी, आजीविका, रोजगार और पीडब्ल्यूडी के लिए आय अर्जन के बारे में जानकारी दी जाती है।
- जिला स्तर पर डीपीओ सदस्यों की त्रैमासिक समीक्षा बैठकों के दौरान, पीडब्ल्यूडी के मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाती है और नेता लोग निर्धारित समय सीमा में स्थानीय मुद्दों को हल करने के लिए एक रणनीति तैयार करते हैं।
- राज्य में स्थापित डीपीओ के संपर्क दौरे के लिए डीपीओ के सदस्यों को ले जाया जाता है ताकि उन्हें सामूहिक आंदोलन के अपने अनुभवों को समझने और सीखने का अवसर प्रदान किया जा सके।
- डीपीओ सदस्य परियोजना के राज्य पैरवी कार्यक्रम में भी भाग लेते हैं, जहां वे राज्य स्तर के अधिकारियों जैसे विकलांगता आयुक्त से मिलते हैं और अपने अधिकारों के लिए पैरवी करते हैं।
- डीपीओ सदस्यों को ब्लॉक और जिला स्तर की बहु-क्षेत्रीय समन्वय बैठकों में भी आमंत्रित किया जाता है जहां वे सरकारी अधिकारियों से मिलते हैं और अपने अधिकारों और हकदारी के लिए पैरवी करते हैं।
- महिला डीपीओ सदस्यों और विकलांग लड़कियों को स्वास्थ्य, स्वच्छता, शिक्षा, आजीविका विकल्प और एसएचजी पर अतिरिक्त प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

सामूहिक मांग पैदा करना

डीपीओ सदस्य ब्लॉक स्तर पर महीने में एक बार और जिला स्तर पर हर तीन महिने में मिलते हैं। ब्लॉक स्तर की बैठकों में, डीपीओ सदस्य अपने गांव/पंचायतों के पीडब्ल्यूडी के मुद्दों को हल करने के लिए चर्चा करते हैं। पीडब्ल्यूडी की मांगों पर जिला स्तर पर चर्चा की जाती है और सरकार के साथ व्यवस्थित पैरवी करने के लिए रणनीति विकसित की जाती है। उन पीडब्लूडी के लिए भी फॉलो-अप किया जाता है जिन्होंने किसी योजना या सेवा के लिए आवेदन कर दिया हो।

जिला और ब्लॉक स्तर पर सरकारी अधिकारियों के साथ निरंतर पैरवी के परिणामस्वरूप, सरकारी अधिकारी और पंचायत प्रतिनिधि पीडब्ल्यूडी की जरूरतों और चिंताओं के बारे में अधिक जागरूक हो गए हैं। डीपीओ सदस्यों को अपने संबंधित ब्लॉक में विभिन्न ग्राम सभाओं/पल्ली सभाओं में आमंत्रित किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पीडब्ल्यूडी अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम हैं या नहीं।

डीपीओ सदस्यों को परियोजना के तहत कार्यान्वित सभी गतिविधियों के लिए आमंत्रित किया जाता है। उदाहरण के लिए, उन्होंने पीआरआई सदस्यों के प्रशिक्षण, अभिभावक परामर्श कार्यक्रम और आशा, एडब्ल्यूडब्ल्यूएस और शिक्षकों के लिए आयोजित प्रशिक्षण में भाग लिया। इसने पीडब्ल्यूडी और विभिन्न हितधारकों के बीच संबंधों को बढ़ावा देने में मदद की है। इन प्रशिक्षणों में पीडब्ल्यूडी की स्थिति के बारे में जानकारी देने के लिए कुछ डीपीओ सदस्यों को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया जा रहा है।

प्रभाव

डीपीओ के गठन से जागरूकता, सुगमता और भागीदारी बढ़ाने, जवाबदेही और साझेदारी को बढ़ावा देने और भेदभाव और असमानताओं में कमी लाने में मदद मिली है। परियोजना वाले पांच जिलों में पीडब्ल्यूडी की आवाजें सुनी जा रही हैं। परियोजना के पहले तीन वर्षों के दौरान डीपीओ सदस्यों के सामूहिक प्रयासों के परिणामस्वरूप कुछ सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। 213 पंचायतों ने पिछले तीन वर्षों के दौरान गरीबी उन्मूलन योजनाओं में पीडब्ल्यूडी के लिए तीन प्रतिशत आरक्षण लागू किया है। मध्यावधि सर्वेक्षण के निष्कर्ष बताते हैं कि इस आरक्षण के परिणामस्वरूप, बालांगीर में 77 प्रतिशत पीडब्लूडी, कैमूर में 69 प्रतिशत, पूर्वी चंपारण में 33 प्रतिशत, बनासकांठा में 37 प्रतिशत और बारवानी में 16 प्रतिशत को इंदिरा आवास योजना के तहत आवास लाभ प्राप्त हुआ है। अब तक, पांच जिलों में डीपीओ के नेताओं ने 6,350 विकलांगता प्रमाण पत्र, 2288 विकलांगता पेंशन और 263 छात्रवृत्ति जारी करने में मदद की है।

शेष पृष्ठ 29 पर

मांग पैदा करने के लिए समूह का निर्माण

- सायन कोंगारी[9], 'एक्शन एड'

सायन कोंगारी ने बताया कि वर्तमान परियोजना के तहत, लोगों को सार्वजनिक कार्यक्रमों और योजनाओं तक पहुंच में सुधार के लिए 6 राज्यों में एक्शन एड काम करता है। पिछले 3 वर्षों में निम्न पर ध्यान केंद्रित किया गया है:

- सरकार की जवाबदेही सुनिश्चित करना
- लोगों द्वारा सामाजिक ऑडिट और सार्वजनिक सुनवाई के इस्तेमाल की वकालत करना
- सरकार को जवाबदेह बनाने और मांग में बढ़ोतरी के लिए सरकार के साथ काम करने के साथ-साथ सामुदायिक संघटन का समर्थन करना
- समूहों में कैडर का निर्माण करना और मजबूत करना

उन्होंने कुछ मुद्दों को उठाया जिन्हें सामूहिक रूप से यूरोपीय संघ द्वारा समर्थित परियोजना 'सार्वजनिक योजनाओं/कार्यक्रमों के बारे में जानकारी तक पहुंच' के कार्यान्वयन भागीदारों द्वारा उठाया जा सकता है:

- सामाजिक सेवाओं और सामाजिक सुरक्षा पर सार्वजनिक खर्च में पर्याप्त वृद्धि सुनिश्चित करना: वर्तमान में, दक्षिण अफ्रीका में जीडीपी के प्रतिशत के रूप में सामाजिक क्षेत्र पर खर्च 15 प्रतिशत और वेनेजुएला में 23 प्रतिशत है। इसके विपरीत, भारत में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में सामाजिक क्षेत्र पर केंद्रीय और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त व्यय लगभग 7 प्रतिशत है। हम मांग करते हैं कि मध्यम अवधि में सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में कम से कम दोगुना होना चाहिए, जो लगभग 15 प्रतिशत है।
- सभी प्रकार के लक्ष्यीकरण को तुरंत समाप्त कर दिया जाना चाहिए, और सभी अधिकार सार्वभौमिक रूप से किए जाने चाहिए।
- सामाजिक सेवाओं का निजीकरण करने के कई उदाहरण हैं। राजस्थान में, कई स्कूलों को बंद कर दिया गया है और विलय किया गया है। हमें सभी प्रकार के निजीकरण, संविदात्मक और सार्वजनिक व्यवस्थाओं को कमजोर करने को रोकने की मांग करनी चाहिए, जो सामाजिक सेवाओं को प्रदान करते हैं। समुदाय को इस पर विचार करना चाहिए कि इस प्रतिकूल रुख को सामूहिक रूप से हल कैसे किया जाए और सरकार को जवाबदेह कैसे बनाया जाए।
- कई सहयोगियों ने समुदाय आधारित निगरानी के लिए तंत्र विकसित करने का प्रयास किया है। इस सिद्धांत को व्यापक रूप से स्वीकार किया जाना चाहिए कि साधारण लोग जो विभिन्न सामाजिक सेवाओं के लाभार्थी हैं, उन्हें सेवाओं की निगरानी में सक्रिय रूप से शामिल होना चाहिए, और इन सेवाओं को लोगों के प्रति प्रभावी ढंग से जवाबदेह बनाना चाहिए। महाराष्ट्र के सैंकड़ों गांवों में सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं की सामुदायिक आधार पर निगरानी के कारण सकारात्मक परिणाम सामने आए हैं। इस तरह की भागीदारी की निगरानी विभिन्न सामाजिक सेवाओं के लिए सार्वभौमिक होनी चाहिए।
- सार्वभौमिक प्रावधान के तहत, यह विशेष रूप से सुनिश्चित करने की जरुरत है कि महिला, दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक समुदाय और घुमंतू समुदाय जैसे विभिन्न पीड़ित और वंचित सामाजिक समूह निश्चित रूप से गुणवत्ता युक्त सामाजिक सेवाओं का उपयोग कर सकें। इसके लिए विशेष ध्यान, निगरानी और उचित मानदंडों को सुनिश्चित करना होगा। ■

9. सायन कॉंगारी पिछले आठ वर्षों से एक्शन एड के साथ कार्यक्रम प्रबंधक, डेमोक्रेटाइजेशन नोइंग एक्टिविस्ट हब के तौर से जुड़ी हुई है। वे अलग अलग नेटवर्क के प्रोजेक्ट व्यवस्थापन, अनुसंधान, नीति वकालत और सुविधा में शामिल हैं।

चर्चा और अध्यक्ष की टिप्पणी

चर्चा

प्रश्नः एसएसके में आपके काम में, क्या आपने योजनाओं तक पहुंचने में विकलांग महिलाओं (डब्ल्यूडब्ल्यूडी) की मदद की है? (नंदिनी रावल, बीपीए)

उत्तरः विकलांग महिलाओं के लिए सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) में कई कार्यक्रम चल रहे हैं। सीएचसी के डॉक्टर ने एक कार्यक्रम आयोजित किया और महिलाओं को साइकिल और अन्य उपकरण दिए गए, जिनकी उन्हें जरूरत थी। (केतकी फ़णसे, एसएसके)

प्रश्नः मुझे यह जानना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूडी को सशक्त बनाने के लिए क्या कुछ किया गया है। (नंदिनी रावल, बीपीए)

उत्तरः अब तक डब्ल्यूडब्ल्यूडी को जानकारी दी गई है कि वे उन योजनाओं का उपयोग कैसे कर सकते हैं और उनके लिए पेश किए गए किसी भी नए कार्यक्रम के बारे में सूचित किया गया है। (केतकी फ़णसे, एसएसके)

प्रश्नः वेलथंगरहिल्फ़ की 'सुशासन' परियोजना में, बजट ट्रैकिंग कौन कर रहा है, वे किन टूल का उपयोग कर रहे हैं और किस अवधि के लिए इसका उपयोग किया जाता है? (स्वप्नी शाह, उन्नति)

उत्तरः बजट ट्रैकिंग पंचायत स्तर पर की जाती है और पंचायत के निर्वाचित सदस्यों को बजट ट्रैकिंग की प्रक्रिया पर प्रशिक्षित किया जाता है। उन्हें पता होना चाहिए कि उनके खाते में आने वाले धन का उपयोग कैसे किया जाता है। एक टीओटी आयोजित किया गया था जिसमें प्रतिभागियों ने बजट को ट्रैक करने के लिए प्रश्नावली का उपयोग करना सीख लिया था, मुख्य रूप से पांच विभागों में आने वाले पैसे के बारे में। 4 जिलों के 17 ग्राम पंचायतों में इस प्रकार का प्रशिक्षण आयोजित किया गया है। इस पहल में बजट, शासन और जवाबदेही केंद्र (सीबीजीए) हमारा भागीदार है और तकनीकी सहायता प्रदान कर रहा है। प्रशिक्षण का संचालन करने के लिए ओडिशा शिवाय सहायता प्रदान कर रहा है। (सस्मिता जेना, वेलथंगरहिल्फ़)

प्रश्नः हमने राजस्थान में बीकानेर में कुछ डीपीओ के साथ काम किया है और हम उन्हें एक्सपोज़र विज़िट के लिए भी ले जाना चाहते हैं। जीएलआरए में, आप अपने समूहों को एक्सपोज़र विज़िट के लिए कहां ले जाते हैं? (अंचल यादव, उर्मूल ट्रस्ट)

उत्तरः हम डीपीओ को राज्य स्तर पर स्थापित संगठनों के दौरे पर ले जाते हैं। गुजरात में अच्छे डीपीओ हैं और हमारे डीपीओ उनके साथ जुड़े हुए हैं। (गौरब सेन, जीएलआरए)

सामान्य टिप्पणियां और प्रश्न

टिप्पणी 1: डीपीओ को मजबूत करने पर केंद्रित जीएलआरए प्रोजेक्ट के परिणामस्वरूप, विकलांग व्यक्ति दिखाई देने लगे हैं। आमतौर पर, वे न तो किसी भी बजट की प्रक्रिया का हिस्सा हैं और न ही वे किसी राजनीतिक इच्छाशक्ति का हिस्सा हैं। श्रवण क्षति, बौद्धिक विकलांगता और मानसिक बीमारी वाले लोगों की तुलना में व्हीलचेयर या बैसाखी का उपयोग करने वाले व्यक्ति या दृष्टिबाधित लोग अधिक दिखाई देते हैं। कम से कम 3 प्रतिशत जनसंख्या विकलांग है। यह मामूली संख्या नहीं है। हालांकि, अधिकांश विकास कार्यक्रमों में, उन्हें अनदेखा कर दिया जाता है। मुझे खुशी है कि यूरोपीय संघ की दो परियोजनाएं विकलांग व्यक्तियों पर केंद्रित हैं; इसने यह उजागर करने में मदद की है कि उनके भी अधिकार हैं। कुछ समय पहले, श्रवण क्षति वाली महिला के साथ मारपीट की गई और उससे बलात्कार किया गया था और कोई महिला संगठन इस मामले को उठाने के लिए तैयार नहीं था क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि वे कैसे मदद कर सकते हैं। वे सबसे पहली और सबसे महत्वपूर्ण बात भूल गए कि वह एक महिला है जिसका शील भंग किया गया है और उसकी श्रवण क्षति एक दूसरा पहलू है। आम तौर पर, विकलांगता प्रमुख हो जाती है और मानवता समाहित हो जाती है। (नंदिनी रावल, बीपीए)

टिप्पणी 2: विधवा पेंशन हर राज्य में अलग-अलग है। हम विधवा पेंशन योजना के तहत गुजरात और आंध्र प्रदेश में विधवाओं को मिलने वाले लाभों और उनके जीवन पर होने वाले प्रभावों को समझने के लिए अध्ययन कर रहे हैं। हम गुजरात में 60 सरकारी योजनाओं के साथ काम कर रहे हैं और उनमें से किसी के पास विधवाओं के लिए मापदंड या प्रावधान नहीं हैं। पेंशन योजनाओं के तहत, विधवाओं को केवल 800 रु. मिलते हैं जो उनके निर्वाह क

लिए पर्याप्त नहीं हैं। जब हमने विधवाओं के साथ काम करना शुरू कर किया, तो हमें पता चला कि उनमें से बहुत सी 'विधवा पेंशन' की परिभाषा/श्रेणी के तहत ही नहीं आती हैं, जबकि वे अधिक वंचित हैं। उनके पास कोई सामाजिक सुरक्षा नहीं है। हमें उन्हें शून्य से नंबर दो पर नहीं लेना पड़ता है, बल्कि हमें उन्हें -2 से शून्य और वहां से दो नंबर तक लाना होता है। कभी-कभी एक ही परिवार में चार अनाथ होते हैं और उनके पास उनके लिए फार्म भरने के लिए परिवार में कोई भी नहीं होता है। इसलिए कमजोर समूहों के भीतर भेदभाव को हल करना महत्वपूर्ण है। (चेतना नंद झा, एफईएस)

टिप्पणी 3: सामाजिक सुरक्षा बजट बढ़ाने के बारे में कोई टिप्पणी थी। मैं यह बताना चाहता हूं कि केंद्र सरकार का कुल बजट सकल घरेलू उत्पाद का 14 प्रतिशत है। इसी तरह, किसी भी राज्य का कुल बजट संबंधित राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 13 से 14 प्रतिशत है। इसका कारण यह है कि कर जीडीपी अनुपात कम है। गुजरात में विधवा पेंशन राज्य प्रायोजित है और हाल ही में सरकार ने इसे संशोधित किया है। (महेंद्र जेठमलानी, पाथे बजट केंद्र)

टिप्पणी 4: हमें यह पता करना चाहिए कि लोगों को क्या जानकारी चाहिए और उन्हें क्या देना चाहिए जो मांग में वृद्धि करने में उनकी मदद करें। पीडीएस के उदाहरण में, इससे पहले बताया गया था कि प्रति परिवार आपूर्ति की गई राशन की मात्रा जितने के वे हकदार हैं उससे कम है; यह इसलिए है क्योंकि मांग आपूर्ति से अधिक है। हमने लोगों को बताया कि पीडीएस की दुकानों ने कितना प्राप्त किया है और कितना वास्तव में वितरित किया गया, यह सारी जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध है। उन्होंने सूचनाओं का इस्तेमाल किया और सार्वजनिक सुनवाई की, डीलरों के जवाब मांगे और उन पर राशन का बैकलॉग देने के लिए दबाव डाला, जिसके वे हकदार थे। इसी प्रकार, ए.डब्ल्यू. के लाभार्थी बच्चों की सूची को भी रखा जाना चाहिए और ए.डब्ल्यू. द्वारा प्राप्त और वितरित सामग्रियों के सभी विवरण समुदाय के साथ साझा किए जाने चाहिए। तब लोग इसका पता लगा सकते हैं कि उन्हें उतना ही मिला है कि नहीं जिसके वे हकदार हैं। यदि उनके पास ऐसी जानकारी हो तभी वे सवाल उठा सकते हैं । (दिलीपसिंह बिदावत, उन्नति)

टिप्पणी 5: मुझे लगता है कि हम अपने समूह को परिभाषित करें। कुछ समूह, एसएचजी हो या अन्य कोई, इसलिए बनते हैं क्योंकि उनके बिना परियोजनाएं आगे नहीं बढ़ सकती हैं। सवाल यह है कि क्या वे परियोजना से आगे जाएंगे या नहीं। एनजीओ की एक पहचान होती है और वे इस पहचान के साथ बड़ी राजनीतिक लड़ाई नहीं लड़ सकते। लोगों का मानना है कि हमने उन्हें संगठित किया है और एनजीओ इसे अपने साथ जोड़ना चाहता है। जो नेटवर्क बनते भी हैं वे कुछ गैर-सरकारी संगठन के साथ जुड़ जाते हैं। इस संदर्भ में एक विरोधाभास है कि समूह उस परियोजना या उस संगठन से परे कभी भी चल नहीं पाएगा। भोजन के अधिकार के पूरे देश में समर्थक हैं और इसके साथ कई एनजीओ जुड़े हुए हैं। हमें केवल स्थानीय समूह और एक ही मुद्दे से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। हमें यह देखना होगा कि मांग में वृद्धि हुई है; बजट पर मांग में वृद्धि; पूरे सामाजिक क्षेत्र की मांग में वृद्धि। इसके लिए, अधिक से अधिक आंदोलनों और व्यापक राजनीतिक विचारों के साथ जुड़े रहने के लिए एनजीओ द्वारा एक सचेत निर्णय लेने की जरूरत है। संघटनात्मक संपर्क संभव है बशर्ते जो लोग समूहों का पोषण कर रहे हैं वे उस प्रयास को करने को तैयार हों और एक अलग पहचान विकसित करने में मदद करने के लिए तैयार हों। (निखिल डे, एमकेएसएस)

टिप्पणी 6: मैं पाठे बजट केन्द्र के लिए प्रस्ताव करना चाहता हूं कि योजनाओं के विश्लेषण के साथ ही घरेलू हिंसा कानून जैसे कानूनों की समीक्षा करें और उनके कार्यान्वयन का आकलन करें। यौन उत्पीड़न समितियों की रचना के बारे में सोचना भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हमें क्षेत्र में कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है। (सुनंदा तायडे, सहियर)

टिप्पणी 7: जब हम सामुदायिक कार्रवाई और जुटाव के बारे में बात करते हैं, तो स्थानीय संदर्भ और स्थानीय संस्कृति को समझना भी उतना ही महत्वपूर्ण है, खासकर जब हम सामुदायिक कार्रवाई की स्थिरता के बारे में बात करते हैं तो। हमारे जैसे संगठनों द्वारा बनाए गए ढांचे हमारे जाने के बाद बने रह भी सकते हैं या नहीं भी रह सकते। यदि हमारे हस्तक्षेप से पहले समुदाय संस्थान मौजूद हैं, तो हम उन्हें विश्वास में ले सकते हैं, उन्हें पुनर्व्यवस्थित कर सकते हैं और एक आम मंच पर आने के लिए उन्हें पुनर्गठित कर सकते हैं। जब हम स्थानीय लोगों को शामिल करते हैं, तो दीर्घकालिक स्थिरता का एक बड़ा मौका होता है। भारत सरकार के दिशा-निर्देश अलग-अलग समितियों की सदस्यता के लिए मानदंड निर्धारित करते हैं। जब इसे बढ़ाने की और कार्यान्वयन करने की बात आती है, तो संस्थाएं दुविधा में होती हैं कि क्या वे एसएचजी या समुदाय आधारित संगठन का चयन करना चाहते हैं। कोई भी नहीं सोचता है कि यदि वे महिला समूह चुनते हैं, तो चाहे समिति रहे या नहीं, यहां तक कि एक महिला भी जो मजबूत और सशक्त है, यह सुनिश्चित करेगी कि समुदाय की कार्यवाही जारी रहेगी। हर गली या मोहल्ले में नागा माता

संघ है; इसी तरह मणिपुर में ऐसी संस्थाएं मौजूद हैं; मादक द्रव्यों के सेवन जैसी स्थानीय समस्याओं से निपटने के लिए सरकार की पहल की परवाह किए बिना, इन संगठनों ने उन्हें हल करना जारी रखा है। (नांग्याल हेकरुजम, एसीटीईडी)

प्रश्नः मेरे पास सभी वक्ताओं के लिए एक आम सवाल है; हर किसी ने, इस या उस तरीके से, इस बारे में बात की है कि हम समुदाय के बीच मांग कैसे पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। यूरोपीय संघ के एक भागीदार के रूप में, हमने पाया है कि सामाजिक सुरक्षा के लिए 7 प्रतिशत से कम राशि उपलब्ध है। लंबे समय से शिक्षा में 6 प्रतिशत की मांग है लेकिन हम इसे प्राप्त करने से बहुत दूर हैं। मांग को निर्धारित करने के लिए एक सरकारी प्रक्रिया है, यानि कौन और कितनों को लाभ प्राप्त करना चाहिए। इसे योजना की प्रक्रिया में शामिल किया जाता है; इसके आधार पर केंद्र और राज्य से आवंटन किया जाता है, जो अंत में वितरित किए जाते हैं। इस प्रक्रिया का प्रबंधन करने के लिए काफी ज़िम्मेदारी जिला स्तर पर नौकरशाही के निचले स्तर को सौंप दी जाती है; यह दिखाने के लिए दबाव रहता है कि मांग वास्तव में जितनी है उससे कम दिखनी चाहिए, ताकि जब प्रभावशीलता की निगरानी की जाए, तो तस्वीर उज्ज्वल दिखे। नौकरशाही के निचले पायदानों को राजनीतिक व्यवस्था से दबाव का सामना करना पड़ता है और हम उनसे उम्मीद नहीं कर सकते कि उनका नागरिकों के प्रति भी दृष्टिकोण होना चाहिए। यह जानना दिलचस्प होगा कि क्या इस मोर्चे पर हस्तक्षेप के कुछ उदाहरण हैं। (शुभ्रा सिंह, द नंदन एंड जीत खेमका फाउंडेशन)

प्रश्नः अधिकांश प्रस्तुतियों में लोगों ने समुदाय संघटन में संघर्ष या विरोध के बारे में बात नहीं की। जब लोग साथ आते हैं, तो एक स्वाभाविक प्रतिरोध और विरोध होता है। हम लोगों के संगठनों और लोगों के संस्थानों के बारे में बात कर रहे हैं, लेकिन अनुभव बताता है कि उनमें से अधिकांश बचे नहीं हैं। यूरोपीय संघ वित्तीय सहायता प्रदान कर रहा है और हम संस्थाएं बना रहे हैं। ईयू परियोजना खत्म होने के बाद इन संस्थाओं को कैसे कायम रखा जाएगा? (अच्युत दास, अग्रगामी)

प्रश्नः हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि सार्वजनिक खर्च में पर्याप्त वृद्धि हुई है? अगर केंद्र विधवा पेंशन के लिए 300 रुपये देता है और हर राज्य में विधवाओं के लिए पेंशन की राशि अलग-अलग इस बहाने से होती है कि सरकार के पास इसके लिए पर्याप्त बजट नहीं है, तो हम इसके लिए सरकार को जवाबदेह कैसे ठहरा सकते हैं? (सायन कोंगारी, एक्शन एड)

वक्ताओं से प्रतिक्रियाएं

1. जब हम डीपीओ बनाते हैं, तो दो स्तर के संघर्ष (टकराव) होते हैं - एक सरकार के साथ होता है और दूसरा समूह के भीतर होता है। उदाहरण के लिए, समूह के भीतर संघर्ष, नेतृत्व की पसंद से संबंधित हो सकता है और जब एक विशेष नेता चुना जाता है तो बैठकों में भाग लेने के लिए प्रतिरोध हो सकता है। सहकर्मी समूह परामर्श आवश्यक है और यह किया जा रहा है। सरकारी अधिकारियों के साथ, संघर्षों को हल करने में समय लगता है। स्थिरता के लिए, जिला स्तर के महासंघों का गठन शुरू हो गया है। दो महासंघों को पंजीकृत किया जा चुका है, गुजरात में एक और एक मध्य प्रदेश में। हम उन्हें विभिन्न सरकारी योजनाओं और परियोजनाओं से जोड़ रहे हैं और उन्हें संसाधन जुटाने में भी मदद कर रहे हैं। हम इसे तीन अन्य जिलों में भी दोहराने की कोशिश कर रहे हैं जहां हमने समूह बना लिया है और परियोजना के समाप्त होने से पहले जिला महासंघ पंजीकृत हो जाएगा। (गौरब सेन, जीएलआरए)
2. मांग और आपूर्ति के बीच की खाई के बारे में एक टिप्पणी थी। हमने यह सुनिश्चित करने के कुछ प्रयास किए हैं कि संसाधनों का आवंटन और वितरण निष्पक्ष और उचित रूप से किया जाए। जब जीपी की कार्यकारी समिति की बैठक होती है, तो विधवा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन आदि के लिए एक सूची तैयार की जाती है। जो पात्र हैं, उनमें से कम से कम 50 से 60 प्रतिशत लाभ प्राप्त करते हैं। हाल के पंचायत चुनाव में, एसएचजी सदस्यों ने विरोध किया था और एक सदस्य पर बमबारी की गई थी; कुछ शक्तिशाली लोगों ने उनके घर पर हमला किया लेकिन उन्हें समूहों का समर्थन प्राप्त था। उनके समर्थन के से उन्होंने चुनाव जीता। राजनीतिक नारा था 'जन बनाम धन'। एक नए विमर्श को लाने के प्रयास किए गए और कुछ हद तक सफलता हासिल की गई। समूहों की स्थिरता एक व्यापक और बड़ी समस्या है। दो साल पहले प्रदान ने जो समर्थन दिया था, वह 90 प्रतिशत तक वापस ले लिया गया है। वे प्रदान से न्यूनतम समर्थन के साथ सदस्यता आधारित संगठन के रूप में काम कर रहे हैं। ईयू परियोजना शुरू होने से पहले इन समूहों का गठन किया गया था। उनका राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन

(एनआरएलएम) के साथ कुछ टकराव है, लेकिन वे इसे बनाए रखने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार से अपनी शर्तों को मनवाने के लिए बातचीत और सौदेबाजी कर रहे हैं। (सुकांत सरकार, प्रदान)

3. हम मुख्य रूप से युवाओं के साथ काम करते हैं। हम यह सुनिश्चित करते हैं कि उनके पास सभी योजनाओं की जानकारी हो और निगरानी करते हैं कि वे इस जानकारी का प्रचार कैसे करते हैं। युवाओं को विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन पर नजर रखने के लिए भी प्रशिक्षित किया जाता है, क्योंकि अगर वे जानते हैं, तो वे जवाबदेही को बढ़ावा देने में मदद ले सकते हैं। (रोशन पठान, एसएसके)
4. लोगों के साथ काम करना और उन्हें जुटाना बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। साथ ही, अगर कोई सरकार के साथ काम कर रहा है, तो लोगों और सरकार के बीच पुल का निर्माण भी बहुत ही चुनौतीपूर्ण है। मैं पहले एक अच्छा उदाहरण साझा करना चाहता हूं। झारखंड में शिक्षा विभाग के प्रिंसिपल सेक्रेटरी (पीएस) हमेशा सीएसओ को सुनने और सहयोग करने के लिए तैयार रहते हैं। झारखंड में आरटीई फोरम शिक्षा विभाग के साथ बहुत निकट सहयोग में काम करता है और इसे विभाग के परिसर के भीतर एक भौतिक स्थान आवंटित किया गया है। सीएसओ और शिक्षा विभाग द्वारा 10,000 स्कूलों (राज्य के कुल स्कूलों का 25 प्रतिशत) का एक संयुक्त अभियान शुरू किया गया था। इसका एजेंडा एक उचित प्रक्रिया के माध्यम से स्कूल विकास योजनाओं को तैयार करना था और सरकार द्वारा योजनाओं को स्वीकृत करवाना था। पीएस ने सभी भाग लेने वाले स्कूलों को एक पत्र जारी किया और उन्हें सीएसओ के साथ काम करने के लिए कहा। कई बार, अधिकारियों के इरादे और प्रतिबद्धता से बदलाव आ सकता है।

   जब हम मांग और आपूर्ति के मुद्दे के बारे में बात करते हैं, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) इसका एक अच्छा उदाहरण है। सार्वभौमिकरण से पहले इस प्रणाली में भ्रष्टाचार था और इसके बाद भी यह जारी रहा। जब तक लोगों को पता नहीं है कि उनके अधिकार क्या हैं और मांग नहीं करते, तब तक कुछ भी नहीं किया जा सकता है। जब लोगों को सशक्त बनाया जाता है, तो यह महत्वपूर्ण है कि वे राजनीतिक प्रक्रिया और सत्ता का हिस्सा बन जाएं। ऐसा विश्वास है कि स्थानीय प्रशासन गैर-दलीय होता है, लेकिन यह सच नहीं है। यहां भी, राजनीतिक दल हावी हैं। शासन प्रणाली में लोगों की भागीदारी और प्रतिनिधित्व दीर्घकालिक समाधान प्रदान कर सकता है। परियोजना आधारित कार्य स्थायी नहीं हो सकता। (सस्मिता जेना, वेलथंगरहिल्फ़)
5. जो लोग पात्र हैं उनके लिए योजनाओं के लाभ प्राप्त करना बहुत कठिन है। फॉर्मों को भरना, सभी आवश्यक दस्तावेज़ों को इकट्ठा करना और दस्तावेजों के गायब होने की स्थिति में फॉलो-अप करना बहुत मुश्किल है। यह भी विडंबना है कि कुबेर बाई नु मामेरू और मंगलसूत्र योजना जैसी कुछ योजनाएं दहेज को प्रोत्साहित करती हैं। जब हम लोगों के साथ इन योजनाओं के बारे में जानकारी साझा करते हैं, तो अप्रत्यक्ष तरीके से, हम दहेज प्रथा को भी प्रोत्साहित कर रहे होते हैं। (सुनंदा तायडे, सहियर)
6. क्षेत्र में काम कर रही एजेंसियां सरकार की पूरक की भूमिका निभाती हैं और कोई भी मौलिक सवाल नहीं पूछती हैं। संगठनों की राजनीतिक निष्ठा कभी-कभी बहुत स्पष्ट हो सकती है; क्षेत्र में, सत्तारूढ़ पार्टी के साथ मेल लाभकारी होता है। हालांकि, संघर्ष के मुद्दों पर थोड़ा सा बातचीत करना अच्छा होगा। संस्थागत नवाचार भी बहुत महत्वपूर्ण हैं। उदाहरण के लिए, क्या आपने वैकल्पिक, गतिशील डाटाबेस निर्माण के बारे में सोचा है; न केवल पंचायत कार्यालय के बाहर बोर्ड, आदि पर प्रदर्शित करें कि कितना पैसा खर्च किया गया है, बल्कि सूचनाओं को सार्वजनिक और ऑनलाइन बनाने से किसी भी व्यक्ति द्वारा उस तक पहुँचा जा सकता है। डेटासेट इतने स्थानीयकृत या स्थिर नहीं होने चाहिए कि यह किसी भी अन्य हितधारक से संपर्क करने के लिए कोई जगह नहीं छोड़े। (डॉ. केशब दास, जीआईडीआर)
7. जब ईयू परियोजना की कल्पना की गई थी, तो जनादेश सूचना तक पहुंच बढ़ाना था। इस परियोजना के हिस्सेदार सभी 14 सहयोगियों ने सहमति व्यक्त की थी कि न केवल जानकारी को समुदाय के साथ साझा किया जाएगा बल्कि योजनाओं के डिजाइन के अनुसार कार्यक्रम बनाए जाएंगे। शौचालय निर्माण की योजना में, लोगों को पहले शौचालय का निर्माण करना था और तब ही वे खर्च की प्रतिपूर्ति के लिए पात्र थे। कुछ राज्यों में, संगठनों द्वारा ठोस प्रयासों के बाद, प्रणाली को उलटा कर दिया गया है। अब एक अग्रिम राशि दी जाती है ताकि लोग अपना खुद का पैसा निवेश किए बिना निर्माण शुरू कर सकें। साथी, अपने स्तर पर, योजनाओं के डिजाइन पर प्रश्न उठाने की कोशिश कर रहे

हैं; कुछ जगहों पर वे सफल होते हैं, जबकि अन्य में संघर्ष चल रहा होता है। जब वितरण प्रणाली में समस्या होती है या भ्रष्टाचार होता है, तो सीधे संघर्ष की स्थिति उत्पन्न होती है। बदलाव के लिए प्रयास समुदाय की साझेदारी में जारी रहेंगे, भले ही वे छोटे हों। (शुभ्रा सिंह, द नंद एंड जीत खेमका फाउंडेशन)

8. गैर-सरकारी संगठन केवल एक सुविधादाता के रूप में काम कर सकते हैं और इसे आगे बढ़ाने के लिए सरकार को एक मॉडल पेश कर सकते हैं। गैर-सरकारी संगठनों के लिए सबसे बड़ी चुनौती सबसे दूर-दराज को एकजुट करने की होती है। जमीनी स्तर पर बहुत भ्रष्टाचार है; उदाहरण के लिए यह देखा गया है कि जब शौचालय निर्माण के लिए लाभार्थियों की सूची तैयार की जा रही थी, तो कुछ लोग सरपंच और सचिव को पहले से ही सूची में शामिल किए जाने के लिए भुगतान कर रहे थे। उन्होंने इस योजना के तहत अपने पहले से निर्मित शौचालयों को निर्माणाधीन दिखाने का प्रस्ताव किया। ऐसी परिस्थितियों से निपटना एक बड़ी चुनौती है। दूसरे, यदि आप किसी भवन के निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्रियों के बारे में सरपंच से पूछें, तो वे तुरंत जवाब दे सकते हैं। लेकिन उन्हें सामाजिक सुरक्षा योजनाओं या लोगों के अधिकारों के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। (अंचल यादव, उर्मूल ट्रस्ट)

अध्यक्ष की टिप्पणी

(प्रो. नवदीप माथुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान, अहमदाबाद)

स्थिरता पर सवाल बहुत महत्वपूर्ण है और यह लंबे समय से सामाजिक क्षेत्र का दमन कर रहा है। सवाल यह बना हुआ है कि जब राज्य की निधि सिकुड़ रही है, तब से धन कहां से आएगा? कई बार, जब कोई अन्य विकल्प नहीं होते हैं या विकल्प इस तरह से साथ नहीं आते कि इस सवाल का जवाब दे सकते हों, तो संगठनों को वहां जाना होता है जहां धन होता है; यह एक घातक दृष्टिकोण है। सत्र की समाप्ति के लिए प्रोफेसर माथुर ने निखिल डे की टिप्पणियों को दोहराया। अधिकारों को खाद्य अधिकार और शिक्षा के अधिकार जैसे व्यक्तिगत अधिकारों में विखंडित करने की राज्य की रणनीति ने शायद एकजुटता को तोड़ने में मदद की है। यदि विकास क्षेत्र के लोग उन सीमाओं से परे काम करने में असमर्थ हैं, तो संभवतः व्यक्तिगत स्तर के संदर्भ से परे एक व्यापक पैमाने पर एक सामूहिक विचार काम नहीं करेगा। यह साझा किए गए अनुभवों से प्रकट होता है। जैसे सरकारी योजनाएं गांव के चौराहे में रखी बॉक्स की तरह होती हैं और सरकार लोगों को चुनौती देती है कि इस बॉक्स से जितना ज्यादा ले सकते हो उतना ले जाओ। इस प्रक्रिया को यह सुनिश्चित करने के लिए सुविधाजनक बनाना कि लोगों को उनके अधिकार मिलेंगे, एक दमनकारी और दर्दनाक प्रयास है, जैसा कि वक्ताओं द्वारा उल्लेखित कई रणनीतियों से स्पष्ट है। लोगों को उनका हक दिलाने के लिए इतने प्रयास और इतने लोगों को शामिल करना बहुत ज्यादा है। यह एक सार्वजनिक संसाधन है; ये सार्वजनिक रूप से दावा की गई और मांगी गई योजनाएं और परियोजनाएं हैं। यह केवल अचानक काम करने की मात्रा को बढ़ाता है, जो निचोड़ने के लिए आवश्यक है - ऐसा करने के लिए भी असाधारण अलौकिक प्रयास, शक्ति और ऊर्जा और बजट की आवश्यकता होती है जिनकी प्रकृति सार्वजनिक नहीं हैं और जो कहीं और से आते हैं। यह मांग पैदा करने की प्रक्रिया के सफल होने के बाद भी केवल काम की बची हुई भारी मात्रा को दर्शाता है। आखिर में, कनेक्टिविटी (संयोजन) एक मुद्दा लगता है। जब कोई इस तरह की लंबी प्रक्रिया से गुजरता है तब आखिरी मील की यात्रा कम दूरी लगती है - लेकिन यह प्रस्तुतियों से स्पष्ट है कि लोगों के पूरे जीवन इस आखरी मील में ही रहते हैं। यह लोगों के लिए जीवन का सबसे बड़ा हिस्सा है और इन संसाधनों को उन मुद्दों में रूपांतरित करना जिसे हम सशक्तिकरण कह रहे हैं - यह सब यहाँ भी हो रहा है। यह फ़ोकस का एक बड़ा क्षेत्र है और कुछ मामूली और सीमांत नहीं है। प्रस्तुतकर्ताओं द्वारा साझा किए गए विचार और साझा किए दृष्टिकोण इस क्षेत्र में ऊर्जा और फोकस बढ़ाने में मदद करेंगे। ■

'महिला किसान सम्मेलन'

15 मार्च और 27 मार्च, 2018 को पाटोदी और सिंधरी, बाड़मेर जिला, राजस्थान में आयोजित

'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' समारोह के तहत 15 मार्च को पाटोदी में और 27 मार्च, 2018 को सिंधरी में आयोजित महिला किसान सम्मेलन अद्वितीय घटनाएं थीं और यह पूरे क्षेत्र में अपनी तरह का पहला आयोजन था। प्रत्येक सम्मेलन में 1500 से अधिक महिला किसानों की उत्साही भागीदारी देखी गई। इन कार्यक्रमों का आयोजन राजस्थान के बाड़मेर जिले के पाटोदी और सिंधरी ब्लॉक के महिला किसानों के नव गठित संघ, जय भीम महिला किसान संगठन द्वारा उन्नति - विकास शिक्षण संगठन के सहयोग से किया गया था। महिला प्रतिभागी बहुत दूर-दूर से और काफी दूर-दराज़ के गांवों से अपनी व्यवस्था से और अपना पैसा खर्च करके आई थी। संघ के नेताओं और अन्य वक्ताओं के वक्तव्य में, सम्मेलनों ने महिलाओं को किसानों के रूप में मान्यता देने और भूमि और संसाधनों के स्वामित्व सहित किसानों के रूप में उनके अधिकार सुनिश्चित करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला।

इस कार्यक्रमों को ब्लॉक और जिले के निर्वाचित प्रतिनिधियों और सरकारी अधिकारियों द्वारा सक्रिय रूप से सहयोग प्रदान किया गया था। प्रियंका मेघवाल (जिला प्रमुख, बाड़मेर) ने दोनों कार्यक्रमों की अध्यक्षता की। रशीदा बानो (प्रधान, पैटोदी) और संतोषी जिंगार (सरपंच, पटोदी) ने सभा को संबोधित किया। सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट (CAZRI), कृषि विज्ञान केंद्र (KVK), कृषि और अन्य विभागों से प्रतिभागियों ने भाग लिया और क्षेत्र के मुख्य बैंक - SBI ने वित्तीय जानकारी के लिए एक स्टॉल लगाया। सिविल सोसाइटी संगठनों के प्रतिनिधियों और सामाजिक कार्यकर्ताओं - भारतीय महिला राष्ट्रीय महिला संघ (NFIW), नई दिल्ली की निशा सिंधु, दलित महिला अधिकार मंच, जयपुर, राजस्थान की गौरी बेन और महिला भूमि स्वामित्व पर कार्य समूह (WGWLO), अहमदाबाद, गुजरात से ज्योत्सना, मजदूर किसान शक्ति संगठन (MKSS) के मुकेश निवासित ने भी सभा को संबोधित किया। इन कार्यक्रमों को प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया - टाइम्स ऑफ इंडिया, राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, नव ज्योति और ज़ी न्यूज द्वारा कवर किया गया था।

महिलाएं कृषि उत्पादन की रीढ़ हैं और कृषि से संबंधित गतिविधियों में 80 प्रतिशत से ज्यादा काम करती हैं - बुवाई, फसल कटाई, बीज एकत्र करना और देखभाल करना, पशुओं की देखभाल करना, फसल पकने के बाद के कार्य आदि। पुरुषों की भूमिका आम तौर पर जुताई, बाड़ लगाना, और खेती के व्यावसायिक पक्ष तक ही सीमित होती है (जैसे बीज की खरीद और अंतिम उपज की बिक्री)। हालांकि, महिलाओं को किसानों के रूप में मान्यता नहीं दी जाती है और उनके द्वारा किए जाने वाले कार्यों को 'अकुशल श्रम' माना जाता है। किसानों के रूप में औपचारिक मान्यता के बिना, महिलाओं को ऋण, मुआवजे, राहत और सरकार द्वारा प्रदान किए जाने वाले अन्य लाभ नहीं मिल सकते।

पश्चिमी राजस्थान में भी, जब पुरुष मजदूरी के लिए प्रवास करते हैं तब महिलाएं कृषि और पशुपालन का कार्य करती हैं। हालांकि, जिस भूमि पर वे खेती करती हैं उसका स्वामित्व उनके पास नहीं होता। वे

औसतन 5 बीघा रेगिस्तान भूमि पर बारानी खेती करती हैं और मुख्य रूप से मूंग, मोठ और बाजरा उगाती हैं। इन किसानों को फसल बर्बाद होने के खतरे का लगातार सामना करना पड़ता है। कृषि के साथ बकरी पालन किया जाता है। राजस्थान के बाड़मेर जिले के पटोदी और सिंधरी ब्लॉक में 1210 दलित महिला सीमांत किसानों का संघ, जय भीम महिला किसान संगठन (JBMKS) इसे बदलना चाहता है। संघ अभी विकसित ही हो रहा है।

'माल्टेसर इंटरनेशनल' और 'जर्मन सहयोग' द्वारा समर्थित 'खाद्य सुरक्षा' सुनिश्चित करने और सूखे की मार झेलने के लिए सशक्त करने' पर परियोजना के हिस्से के रूप में संघ को उन्नति के द्वारा प्रोत्साहित किया जाता है। इस फेडरेशन (संघ) को बेहतर और टिकाऊ कृषि प्रथाओं को शुरू करने, भूमि और जल संसाधन विकास के लिए सरकारी कार्यक्रमों तक पहुंच और जमीन की प्रति इकाई में खेती की लागत कम करने और फसल उत्पादकता में वृद्धि के लिए स्वदेशी बीज उत्पादन में आत्म-निर्भरता के उद्देश्य से बढ़ावा दिया गया था। फसल के बाद की प्रथाओं और बेहतर बाजारों तक पहुंच के माध्यम से उपज के लिए बेहतर कीमतें प्राप्त करने में संघ भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। इनके अलावा, संघ महिलाओं के लिए किसानों का दर्जा और किसानों के रूप में उनके अधिकारों मान्यता चाहता है। संघ को पता है कि कृषि का भविष्य और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के SDG-2 को प्राप्त करने के प्रयासों की सफलता छोटे और सीमांत किसानों के हाथों में है और पानी के कुशल और आर्थिक उपयोग के साथ सतत कृषि प्रथाओं का उपयोग करने में है। मारवाड़ी भाषा में संघ का उद्देश्य इस प्रकार से उचित ही है -

'आधो खरचो, उपज दोगुनी,
मिले दोगुना दाम,
जे इको करले मरुधारा री महिला किसान'। ■

पृष्ठ 21 का शेष

2016 में बिहार पंचायत चुनाव में, 31 डीपीओ नेताओं ने चुनाव लड़ा और उनमें से सात जीते। उनकी प्रेरणा और उनके समुदाय का नेतृत्व करने का उत्साह स्पष्ट है। बिहार में डीपीओ के नेताओं की वकालत के परिणाम स्वरूप कैमूर और पूर्वी चंपारण जिलों के ब्लॉक स्तर पर विकलांगता प्रमाण पत्र जारी किए गए। कैमूर जिले के सभी छह ब्लॉक में 2015 में मेगा विकलांगता प्रमाण पत्र शिविर आयोजित किए गए थे। 187 पीडब्लूडी ने विकलांगता प्रमाणपत्र प्राप्त किए। एसपीजे टीम के साथ डीपीओ सदस्यों को मध्य प्रदेश के बारवानी जिले में स्कूलों में रैंप की गुणवत्ता देखने और रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होंने स्वच्छ भारत मिशन के लिए पीडब्ल्यूडी के लिए मॉडल सुलभ शौचालय के निर्माण में तकनीकी सहायता प्रदान की थी।

पीडब्ल्यूडी की एक सामूहिक इकाई के रूप में, डीपीओ ने उनके अधिकारों के लिए प्रभावी ढंग से वकालत की है। इस परियोजना ने उन्हें अपने मुद्दों पर चर्चा करने और उन सहयोगी समूहों का विकास करने के लिए एक मंच दिया है जो उनके लिए बात करेंगे और उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे। इन समूहों में नेतृत्व उभर रहा है और वे दूसरे गांवों में महिलाओं और बच्चों जैसे अन्य उपेक्षित समूहों के लिए भी वकालत कर रहे हैं। गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर क्षमता के निर्माण से पीडब्लूडी के अधिकारों तक पहुंच के लिए आंदोलन की चिरंतनता में योगदान मिलेगा।

प्रस्तुति के प्रमुख बिंदु

1. जिला और ब्लॉक स्तर पर सरकारी अधिकारियों के साथ सतत पैरवी ने उन्हें और साथ ही पंचायत प्रतिनिधियों को विकलांगों की जरूरतों और चिंताओं से अवगत कराने में मदद की है।
2. डीपीओ सदस्यों को उनके संबंधित ब्लॉक में विभिन्न ग्राम सभाओं/पल्ली सभाओं में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया जाता है ताकि यह पता लगाया जा सके कि पीडब्ल्यूडी अपने अधिकारों का उपयोग करने में सक्षम हैं या नहीं।
3. डीपीओ सदस्यों को परियोजना के तहत लागू सभी गतिविधियों के लिए आमंत्रित किया जाता है। इसने पीडब्ल्यूडी और विभिन्न हितधारकों के बीच रिश्ते को बढ़ावा देने में मदद की है।
4. डीपीओ के गठन से जागरूकता बढ़ाने, सुगमता और भागीदारी में मदद मिली है, जवाबदेही और साझेदारी बढ़ा दी है और भेदभाव और असमानताओं में कमी आई है।
5. इस परियोजना ने विकलांग व्यक्तियों को उनके मुद्दों पर चर्चा करने और उन सहयोगी समूहों को विकसित करने के लिए मंच दिया है जो उनके लिए बोलेंगे और उनके अधिकार प्राप्त करने के लिए उनका मार्गदर्शन करेंगे।
6. गांव, ब्लॉक और जिला स्तर पर क्षमता के निर्माण से पीडब्लूडी के अधिकारों तक पहुंच के लिए आंदोलन की चिरंतनता में योगदान मिलेगा। ■

'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के संदर्भ में सम्मेलन

13 मार्च, 2018, पोशीना, साबरकांठा जिला, गुजरात

गुजरात में साबरकांठा जिले के पोशीना में एपीएमसी, लाम्बडीया पंचायत में जिला पंचायत-साबरकांठा, 'उन्नति' और 'यूरोपीय संघ' के सहयोग से 'अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस' के सदंर्भ में एक सम्मेलन का आयोजन दिनांक 13 मार्च 2018 को किया गया।

इस सम्मेलन में आमंत्रित वक्ताओं में सुश्री सोफिया खान, निदेशक, 'सफ़र', अहमदाबाद; सुश्री जया वाघेला, उप प्रबंध निदेशक, 'गुजरात राज्य महिला सेवा सहकारी संघ लिमिटेड'; श्री महेश पटेल, उप निदेशक, 'विकसत'; श्री कौशिक मोदी, जीएएस, उप-जिलाधीश और एसडीएम खेडब्रह्मा; श्री हर्ष व्यास, आईएएस, डीडीओ, जिला साबरकांठा; श्री पी. स्वरूप, आईएएस, जिला कलेक्टर, साबरकांठा; सुश्री दीपा सोनपाल, कार्यक्रम समन्वयक, 'उन्नति' और पोशीना के तालुका स्तर के अधिकारी शामिल थे। इस सम्मेलन में लगभग 1100 प्रतिभागियों में महिला नागरिक नेता, लाभार्थी, आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, आशा कार्यकर्ता, महिला निर्वाचित प्रतिनिधि, सीएसओ के सदस्य, एसएचजी के सदस्य, विभिन्न संबंधित सरकारी विभागों के अधिकारी, पास के कॉलेजों और विद्यालयों की छात्राएं, शिक्षिकाएं, जिला और तालुका/ब्लॉक स्तर के निर्वाचित प्रतिनिधि और समुदाय के सदस्य आदि शामिल थे। महिला समुदाय के नेताओं और किशोरियों ने शिक्षा और स्वास्थ्य योजनाओं तक पहुंच; डायन बताना और आत्महत्या जैसी महिलाओं के खिलाफ हिंसा; और संगठनों का गठन करके और मजबूत करके महिलाओं को सशक्त करने और उनकी आवाज बुलंद करने की आवश्यकता पर सम्मेलन में अपने अनुभव और चुनौतियों को साझा किया।

सम्मेलन में विभिन्न सरकारी विभागों और योजनाओं की आईईसी सामग्री प्रदर्शित करने वाली स्टाल लगाई गई थी, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य, आईसीडीएस, डीसीपीयू, केएएलपी उत्पादक कंपनी लिमिटेड, विकसत (टाटा ट्रस्ट द्वारा), एपीएमसी और उन्नति ने भाग लिया था। प्रतिभागीगण पंजीकरण और लंच के दौरान स्टॉल देखने आए थे। महिला सशक्तिकरण के लिए गाने लोक सेवा युवा ट्रस्ट, ईडर से शंकरभाई वणकर और उनकी टीम ने गाए थे।

सत्र-1: उद्घाटन सत्र

यह सत्र एक स्थानीय आदिवासी गीत और महिला सशक्तिकरण पर एक गीत के साथ शुरू हुआ। स्वागत संबोधन सुश्री दीपा सोनपाल, कार्यक्रम समन्वयक, उन्नति द्वारा किया गया। प्रतिभागियों और आमंत्रित अतिथियों का धन्यवाद करते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि यह कार्यक्रम जिला पंचायत, उन्नति और यूरोपीय संघ की एक संयुक्त पहल थी। जेंडर मुद्दों पर संगठन के काम की संक्षिप्त पृष्ठभूमि और सार्वजनिक योजनाओं के बारे में जानकारी तक पहुंच के बारे में चार साल पहले तालुका में जो काम शुरू किया गया था उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी दी गई। 'उन्नति' हमेशा जेंडर समानता पर प्रतिबद्ध रही है और दो दशक पहले राज्य जेंडर नीति (नारी गौरव नीति)

बनाने वाली समिति की सदस्य भी थी। एक संगठन के रूप में उन्नति समावेश के मुद्दों और विशेष रूप से विकास प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी - आदिवासी, दलित, अल्पसंख्यक और विकलांग महिलाओं के बारे चिंतित रही है। अनुभव बताता है कि बीपीएल परिवार को अपनी मूलभूत जरूरतों को पूरा करने के लिए वर्ष में केवल 70,000 रु. की आवश्यकता होती है। अगर सरकारी योजनाएं समय पर प्राप्त हो जाएं तो बीपीएल परिवार को प्रति वर्ष 3,00,000 रुपये तक लाभ मिल सकता है। कई बाधाओं को दूर करने की जरूरत है लेकिन इनका समाधान तभी किया जा सकता है जब मांग पैदा करके योजनाओं का लाभ प्राप्त करने के लिए समुदाय द्वारा प्रयास किए जाएं।

प्रभावी सेवा प्रदान करने के लिए जमीनी स्तर पर जवाबदेही और पारदर्शिता सुनिश्चित करने में निर्वाचित प्रतिनिधियों की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है। गुजरात में हाल ही में पीईएसए (पेसा) नियमों ने ग्राम सभा को अपार शक्ति प्रदान की है, लेकिन इन मंचों में महिलाओं की बहुत कम भागीदारी है। सार्वजनिक क्षेत्र में और निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की कम भागीदारी के कई कारण हैं। कई कारणों में से एक काम का भारी बोझ है (महिलाओं के लिए लगभग 17 घंटे और पुरुषों के लिए 6-8 घंटे)।

वक्ता ने 18वीं शताब्दी में महिलाओं के आंदोलन के इतिहास के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी, जिसमें यूरोप में देश के नागरिक के रूप में मतदान करने के अधिकार की मांग करना, उसी समय संयुक्त राज्य अमेरिका में काम की बेहतर परिस्थितियों की मांग करना और भारत में स्वतंत्रता के बाद भेदभाव विरोधी कानूनों को लागू करना शामिल है। फिर भी, जेंडर समानता के लक्ष्य को हासिल करने के लिए लंबा रास्ता तय करना बाकी है। गणमान्य व्यक्तियों का हार्दिक स्वागत करने और महिलाओं के आंदोलन के बारे में जानकारी देने और महिला दिवस को मनाने के महत्व के बारे में बताने के बाद कार्यक्रम का संक्षिप्त विवरण दिया गया। इस कार्यक्रम की शुरुआत गणमान्य व्यक्तियों द्वारा दीप प्रज्वलित करके की गई जिसके बाद महिला सशक्तिकरण पर एक गीत गाया गया।

सत्र-2: समुदाय की महिलाओं की कहानियों को साझा करना

समुदाय की कुछ महिलाओं और पुरुषों ने इस बारे में अपनी समझ संक्षेप में साझा की। एक नागरिक नेता मोडाभाई ने प्रथागत कानूनों और लोकाई चारा जैसी प्रथाओं को सुधारने की आवश्यकता और महिलाओं को सार्वजनिक क्षेत्र में भाग लेने के लिए पुरुषों के सहयोग की ज़रूरत पर जोर दिया। उर्जा घर की सोनलबेन ने आदिवासी महिलाओं की स्थिति पर बात की जहां डायन होने का आरोप लगाना जैसी प्रथागत रिवाज और आत्महत्या जैसे सामाजिक दबाव प्रचलित हैं। उन्होंने तालुका में शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने यह भी कहा कि महिला निर्वाचित प्रतिनिधियों के लिए ग्राम पंचायतों में 50 प्रतिशत आरक्षण है, इसलिए महिलाओं नेताओं को अपने पतियों और ससुरों पर भरोसा करने की बजाय अपनी भूमिका और जिम्मेदारियों को पूरा करना होगा। एक विकलांग महिला, पिंकीबेन ने विकलांगता पहचान पत्र और बस पास प्राप्त करने में अपने अनुभवों और कठिनाइयों के बारे में बताया। अंततः इसे प्राप्त करने से पहले उसे हिम्मतनगर में इधर से उधर धक्के खिलाए गए। पोशीना में कॉलेज के दूसरे वर्ष की छात्रा हंसाबेन ने अपने गांव से तालुका कॉलेज तक परिवहन सुविधा मांगते हुए जिला कलेक्टर, साबरकांठा को पत्र लिखने का अपना अनुभव साझा किया, क्योंकि उन्हें प्रत्येक दिन कई किलोमीटर चलना पड़ता है। आईटीआई में पढ़ने वाली छगनीबेन ने बताया कि कैसे बेरोजगार होने के बावजूद उनके पिता ने 12वीं कक्षा के बाद पढ़ाई जारी रखने के लिए उसे सहयोग दिया है। यह शिक्षा ही है जो हमें अपने जीवन की गुणवत्ता को बेहतर करने में मदद करेगी। फिर हमें दूसरों पर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। अवनीबेन ने अपने अनुभव को साझा किया कि उन्हें आरएसबीवाई कार्ड के बारे में कैसे पता चला और वह अपने परिवार के स्वास्थ्य देखभाल के लिए इसके लाभ कैसे प्राप्त कर पाई।

विजयनगर की नागरिक नेता विमलाबेन ने बताया कि वे कैसे

समुदाय में सरकारी योजनाओं के बारे में जागरूकता बढ़ा रही है और लाभार्थियों को योजनाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए सक्षम बना रही हैं। विजयनगर की एक अन्य नागरिक नेता अन्नाबेन ने आरटीआई दायर करने के अपने अनुभव को बताया और वे अभी भी उसके जवाब की प्रतीक्षा कर रही हैं। उन्होंने यह भी समझाया कि कैसे इस देश के नागरिकों के रूप में सभी महिलाएं आरटीआई फाइल कर सकती हैं और सरकारी सेवा संस्थानों जैसे आंगनवाड़ी, पीडीएस, एमजीनरेगा और ग्राम पंचायतों को समुदाय के लिए जवाबदेह और योजनाओं के समय पर कार्यान्वयन के लिए दबाव डाल सकती हैं। उन्होंने न केवल अपने और अपने परिवार के लिए बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए निडर रूप से काम करने की आवश्यकता पर जोर दिया, क्योंकि हमारे बच्चों का अच्छी तरह से पोषण और अच्छी तरह से शिक्षित होना चाहिए ताकि वे सम्मानजनक जीवन जी सके। परिश्रम सेवा ट्रस्ट, हिम्मतनगर की सीएसओ नेता, पकिताबेनने नागरिक सहयोगी के रूप में घर से बाहर निकलने और सहकारी सोसायटी को पंजीकृत करने के लिए महिलाओं को संगठित करने और उनके आयोजन के बारे में बताया। इस सहकारी समिति में अब समाज के सभी वर्गों की 250 महिलाएं हैं और वे केवल बचत और ऋण सोसायटी से आगे बढ़कर आजीविका पैदा कर रही हैं ताकि महिलाओं को अपने जीवन पर अधिक नियंत्रण मिले और वे स्वयं अपने निर्णय ले सकें। उन्होंने जोर देकर कहा कि महिलाओं में गहन आंतरिक क्षमता होती है और उन्हें इसका प्रदर्शन करना चाहिए। जब कई महिलाएं संगठित होती हैं और अपनी आवाज उठाती हैं तो हम पर्वतों को भी हिला सकती हैं। विजयनगर की एक पूर्व महिला सरपंच, गंगाबेन ने सार्वजनिक क्षेत्र में कार्य करने के अपने अनुभव को साझा किया। सार्वजनिक क्षेत्र में पहला कदम उठाना हमेशा मुश्किल होता है और मुझे भी इस कठिनाई का सामना करना पड़ा था। सबको सब कुछ पता नहीं होता लेकिन हमें इसके बारे में सीखने और कार्य करने की कोशिश करनी चाहिए। जालेटी ग्रुप ग्राम पंचायत में मैंने ऐसे काम किया जैसे कि सभी मेरे बच्चे हैं अतः हमें हमारी सीमाओं में रहकर सर्वश्रेष्ठ करने की कोशिश करनी चाहिए।

सत्र-3: गणमान्य लोगों द्वारा ज्ञान की बातें

अहमदाबाद में एक गैर सरकारी संगठन, सफ़र की निदेशक, सोफिया खान ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर महिला दिवस मनाने की प्रासंगिकता बताने के साथ हमारी उपलब्धियों को गिनाते हुए और जो भी किया जाना बाकी है, उसके लिए योजना बनाने की जरूरत के साथ अपना भाषण शुरू किया। वे वर्षों पहले पोशीना, शामलाजी, अम्बाजी के इन भागों की यात्रा कर चुकी हैं और यहां सोनलबेन द्वारा वर्णित डायन आरोपित करने की प्रथाओं के बारे में दोहराया। आखिरकार श्यामलाजी में इस प्रथागत रिवाज के खिलाफ जनहित याचिका दायर की गई थी। महिलाओं को चुड़ैल (डायन) क्यों माना जाता है, यह ऐसा कुछ है जिस पर हमें एक समुदाय के बारे में सोचने या मनन करने की आवश्यकता है? हमें ऐसी कुप्रथाओं पर सवाल उठाने की जरूरत है जिनका उद्देश्य आदिवासी क्षेत्र में महिलाओं को बदनाम करना है। यह एक लोकप्रिय ग़लतफ़हमी है कि शहरी इलाकों की महिलाओं की तुलना में आदिवासी महिलाएं विरोध नहीं करती हैं। ये पारंपरिक प्रथाएं और गलत धारणाएं केवल महिलाओं के लिए ही हानिकारक हैं। कोई भूत या बुरी आत्माएं मौजूद नहीं हैं और देश की कानूनी प्रणाली में हानिकारक प्रथाओं को चुनौती दी जानी चाहिए। हमें हमारी मान्यताओं पर सवाल उठाने की जरूरत है क्योंकि इस देश में बहुत से लोगों की हत्या की जाती है, लेकिन इन व्यक्तियों के भूत वकीलों या अपराधियों के शरीरों में क्यों नहीं आते हैं? हमें अपने दिमागों में मनन और चिंतन करने की आवश्यकता है कि धरती पर भूत या बुरी आत्माओं जैसे कोई तत्व नहीं हैं। इस सम्मेलन का उद्देश्य सरकारी योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को उजागर करना है। अगर शांति होगी तो विकास प्रभावी होगा, शांति केवल तभी होगी जब न्याय होगा और न्याय तभी संभव है, जब समानता होगी।

समानता घर से घरेलू संबंधों के भीतर शुरू होती है। यदि घर के भीतर शोषण और असमानता है तो घर से बाहर असमानता का सवाल कैसे उठाया जा सकता है? परिवर्तन स्वयं से शुरू होता है। आज हम इतने सारे लोग इकट्ठा हुए हैं, तो हम सभी प्रतिज्ञा करें कि नागरिकों के रूप में समानता की मांग करने से पहले, हम अपने परिवारों के भीतर पुरुषों और महिलाओं के बीच समान संबंध सुनिश्चित करेंगे। हमें कानूनी प्रणाली और विशेष रूप से पुलिस

विभाग के भीतर सोच को बदलने की जरूरत है कि आदिवासियों, मुस्लिम, दलित और गरीब महिलाओं की शिकायतें और मुद्दे वास्तविक और असली हैं और उन पर ध्यान देना चाहिए और उन्हें हल किया जाना चाहिए। अतः सभी विभागों से एक विनम्र अनुरोध है कि वे अपने अधिकारियों के लिए संवेदीकरण कार्यक्रम चलाएं।

इस देश के सभी कानून इसके सभी नागरिकों के लिए समान आधार पर सुलभ होने चाहिए। भारतीय संविधान इस देश के सभी गरीबों और महिलाओं को मुफ्त कानूनी सहायता की गारंटी देता है। तालुका स्तर के न्यायालय में एक आवेदन पत्र उपलब्ध है। भरा हुआ आवेदन जमा होने के आठ दिनों के भीतर आवेदक या शिकायतकर्ता को नामित वकील के साथ एक पत्र प्राप्त होगा। फिर अदालत में मामला दायर किया जा सकता है। एक प्रचलित मिथक है कि कुछ कानून आदिवासी महिलाओं के लिए लागू नहीं हैं। लेकिन मैं यहां बताना चाहूंगी कि भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) के तहत सभी कानून इस देश की सभी महिला नागरिकों पर लागू होते हैं और हम सभी प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। आईपीसी की धारा 125 के तहत, एक आदमी की पहली पत्नी अपने पति के खिलाफ अपने लिए और 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए भरण-पोषण की मांग करते हुए दावा कर सकती है। इसलिए सरकार और इस देश के कानून हमारे अपने जीवन की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए हैं, तो इनका उपयोग क्यों न करें? यह एक सुझाव है कि इस क्षेत्र की महिला अपनी क्षमता का निर्माण कर सकती है और अपना खुद का न्याय पंच बना सकती हैं। हम सभी को गरिमा के जीवन जीने की जरूरत है, जिसके लिए हमें पहले एक पूर्ण जीवन जीने का सपना देखना शुरू करना चाहिए। हम सभी को प्रगति/विकास के लिए सामूहिक रूप से दबाव बनाने की जरूरत है। चूंकि हम इस अवसर पर आज यहां इकट्ठा होने के लिए घर से बाहर निकली हैं, इसलिए मैं सभी महिलाओं और लड़कियों को आगे बढ़ने, आगे बढ़ने, तालुका जाने, जिला स्तर पर हिम्मतनगर, अहमदाबाद में राज्य स्तर तक, न्याय की तलाश करने और अपने सपनों को पूरा करने के लिए दुनिया में बाहर निकलने के लिए प्रोत्साहित करती हूं।

श्री हर्ष व्यास, जिला विकास अधिकारी, साबरकांठा ने जोर देकर कहा कि ऐसे कार्यक्रम जहां महिलाएं बड़ी संख्या में इकट्ठा होती हैं, वे ऐसे पिछड़े क्षेत्रों में महिलाओं में जागरूकता पैदा करने में काफी मदद करते हैं। सभी गैर सरकारी संगठन सरकारी विभागों द्वारा निभाई गई भूमिका को पूरा करने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एनजीओ की भूमिका वहां से शुरू होती है, जहां सरकारी विभागों की भूमिका समाप्त होती है।

जिला प्रशासन ने कुपोषण से निपटने की जिम्मेदारी खुद पर ली है। बच्चे की जरूरतों और विकास में साथ देने की जिम्मेदारी जन्म देने वाली माता और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की है। कई योजनाएं हैं जिनका उद्देश्य बच्चों के साथ-साथ गर्भवती महिलाओं के पोषण स्तर को बढ़ाना है। सभी गर्भवती महिलाएं मुफ्त संस्थागत प्रसव और बच्चे के जन्म के बाद की देखभाल की हकदार हैं। सभी सरकारी विभाग समुदाय को अपनी सेवाएं देने के लिए उत्सुक हैं। यहां पर मौजूद जिला, तालुका और ग्राम पंचायत स्तर के सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों से विशेष अनुरोध है कि वे सुनिश्चित करें कि आंगनवाड़ी का कामकाज नियमित रूप से चलता रहे। यह निर्वाचित प्रतिनिधियों और समुदाय के सदस्यों का कर्तव्य है कि सामुदायिक स्तर पर सेवाएं प्रदान करना सुनिश्चित हो। गैर सरकारी संगठन और सरकारी अधिकारी बाहरी व्यक्ति हैं और उनकी सीमित भूमिका होती है क्योंकि वे तालुका में कभी-कभी आते हैं। लेकिन सार्वजनिक योजनाओं और सेवाओं के लाभ प्राप्त करने के लिए स्थानीय स्तर पर समुदाय का सहयोग आवश्यक है। आंगनवाड़ी में आने वाले बच्चे हमारे बच्चे हैं। एक गर्भवती महिला आंगनवाड़ी में खुद को पंजीकृत करती है तो वह और उसका बच्चा कई सरकारी सेवाओं के लिए हकदार होते हैं जिन्हें धनराशि में परिवर्तित करें तो यह करोड़ों तक पहुंचती है। कृपया मुख्य रूप से आँगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ संबंधों को बनाए रखने के बारे में नहीं सोचें जो रिश्तेदार हो सकता है, लेकिन सोचें कि यदि आंगनवाड़ी नियमित रूप से नहीं खुले और बच्चों की सेवा नहीं करे तो इसका मतलब हमारे बच्चों को वंचित किया जा रहा है।

अगर सेवाओं को प्रदान करने से संबंधित किसी भी प्रकार की शिकायत हो तो कृपया संबंधित विभागों के ध्यान में लायें। हमारे कई अधिकारी अक्सर तालुका का दौरा करते हैं और अगर आपको प्रशासन पर भरोसा है तो ऐसा क्यों है कि अनियमितताओं को हमारे ध्यान में नहीं लाया जाता। मुझे यह पहलू समझ में नहीं आता। हमें समुदाय से प्राप्त होने वाली शिकायतों का निवारण करके खुशी होगी।

श्री पी. स्वरूप, आईएएस, जिला कलेक्टर, साबरकांठा ने अपने भाषण की शुरूआत इससे की कि पोशीना माता-पिता के सबसे कम उम्र के बच्चे की तरह है, क्योंकि इसे तीन साल पहले ही तालुका का दर्जा दिया गया है। यह एक बढ़ते बच्चे की तरह है जो कुछ भी नहीं कहता या कुछ भी नहीं पूछता या मांग नहीं करता। सांस्कृतिक रूप से पोशीना के लोग कम बोलते हैं और अपनी मांग और शिकायतें नहीं रखते। उन्होंने व्यक्तिगत रूप से तालुका का दौरा करने में बहुत समय बिताया है और इन मुद्दों को समझने और उन्हें हल करने की कोशिश की है। डीडीओ महोदय ने आंगनवाड़ी के नियमित रूप से काम करने का मुद्दा उठाया है। अगर आँगनवाड़ी दिन में 12 बजे खुलें और 1 बजे बंद हो जाएं तो वे समुदाय की सेवा कैसे करेंगी? समुदाय भी अपनी शिकायतों को बताने के लिए तैयार नहीं है इसलिए हम कार्रवाई करने में असमर्थ हैं। जो बच्चा रोता है उसे चॉकलेट दिया जाएगा! इसलिए मांग पैदा करने की आवश्यकता है। अधिक मांगेंगे तो आपको थोड़ा-बहुत दिया जाएगा। इसलिए यह अनुरोध है कि अपनी शिकायतें भेजें और हम उन्हें दूर करने की पूरी कोशिश करेंगे।

इस क्षेत्र में 'रूमाल प्रथा' जैसे बहुत सारे सामाजिक रिवाज हैं जिसका पालन तब करना पड़ता है जब कोई मर जाता है, बदला लेने के लिए 'चधोरु' नामक एक सामाजिक प्रथा होती है और जब कोई बीमार पड़ जाता है तो उन्हें 'भुवा' नामक ओझा के पास ले जाया जाता है। आप भले ही भुवा के पास जाएं लेकिन पहले कृपया डॉक्टर के पास भी जाएं। सभी संबंधित सरकारी विभागों को दो चीजों पर नजर रखने की जरूरत है। सबसे पहले, किसी भी माता का वजन 45 किलोग्राम से कम नहीं होना चाहिए। आंगनवाड़ी और एफपीएस में वजन करने की मशीनें हैं। यदि गर्भवती माता का स्वास्थ्य खराब है तो पैदा होने वाला बच्चा भी कमजोर होगा और भावी पीढ़ी कमजोर हो जाएगी।

दूसरे, मां के हीमोग्लोबिन का स्तर कम से कम 7 से कम नहीं होना चाहिए। हमने उच्च खतरे वाली 6000 माताओं की सूची तैयार की है जिन्हें प्रसव के दौरान अपनी जान गंवानी पड़ सकती हैं। मातृ मृत्यु का सबसे सामान्य कारण 18 साल से कम की गर्भवती माता होना, माता का वजन 45 किलो से कम होना और हीमोग्लोबिन का स्तर 7 एमएमएस से कम होना है। इन तीनों कारणों को रोका जा सकता है और हम इन पर काम कर सकते हैं। हम कुपोषित हैं इसलिए हम गरीब हैं यह मिथक है। इसके लिए आंगनवाड़ी द्वारा प्रदत्त पौष्टिक भोजन का सेवन किया जाना चाहिए। दूसरा हमें अपने क्षेत्र में परंपरागत रूप से उगाई जाने वाली खाद्य फसलों का सेवन करना चाहिए। यूनिसेफ के एक अध्ययन का कहना है कि कुपोषण इसलिए है क्योंकि भोजन का सेवन कम है। हमें अच्छी तरह से खाना चाहिए - अगर हम दो चपाती खा रहे हैं तो तीन खाएं और तीन खा रहे हैं तो चार खाएं।

आदिवासी तालुकों में 'दूध संजीवनी' की एक योजना है, इसके तहत आंगनवाड़ी और स्कूलों में दूध दिया जाता है। बीच में यह दो महीने के लिए रुक गयी थी। किसी भी सरकारी विभाग ने इस बारे में मुझे नहीं बताया, न ही आँगनवाड़ी कार्यकर्ताओं ने, न ही एफएचडब्ल्यू ने, न ही स्कूल/शिक्षा विभाग ने। मुझे तब बताया गया था जब मैंने क्षेत्र में इस तरह के एक कार्यक्रम में भाग लिया। फिर इसे एक सप्ताह के भीतर पुनः आरंभ किया गया था। इसलिए अनुदान उपलब्ध है, इच्छा है लेकिन कुछ बाधाओं के कारण शायद कार्यान्वयन में त्रुटि है। हाल ही में मिड डे मील प्रोग्राम के माध्यम से चना नहीं दिया जा रहा था। इस तरह की त्रुटियों को हमारे ध्यान में लाया जाना चाहिए। पिछड़े तालुकों में आखिरी छोर तक पहुंचना एक समस्या है। लेकिन सभी

मुद्दों को हमारे ध्यान में लाया जाना चाहिए। मांग पैदा करने की जरूरत है।

उज्वला योजना नामक एक अन्य योजना है। इस साइट पर गैस सिलेंडरों के उपयोग के बारे में एक स्टॉल लगाई गई है। पोशीना इस जिले में सबसे छोटा और अंतिम तालुका है, लेकिन इसमें लाभार्थियों की संख्या सबसे अधिक है। इस योजना का लाभ उठाने के लिए अत्यधिक अनिच्छा है। चूंकि इसमें कोई मांग नहीं है इसलिए हमें अनुदान वापस भेजना होगा। हम भी हमारे उच्च अधिकारियों के प्रति उत्तरदायी हैं। अगर गैस सिलेंडरों के उपयोग से संबंधित मिथक हैं तो हम इसे यहां प्रदर्शित कर रहे हैं। जिन नामों को लाभार्थियों के रूप में शामिल किया गया है उन सभी परिवारों से अनुरोध है कि वे गैस सिलेंडरों को स्वीकार करें। केवल एक मामूली अंशदान देना है।

अपने भाषण के अंत में कलेक्टर ने महीने के अंतिम सप्ताह में तालुका में आयोजित होने वाले विकलांग शिविर की घोषणा की। उन्होंने परिवार नियोजन के बारे में भी बात की। उन्होंने कहा कि साबरकांठा में लिंग अनुपात 897:1000 जीवित जन्म है। लेकिन यह मुद्दा पोशीना में नहीं है। लेकिन प्रत्येक परिवार में काफी संख्या में बच्चे हैं। लेकिन जब हम पूछते हैं कि बच्चे किस कक्षा में पढ़ रहे हैं तो कोई जवाब नहीं मिलता। हमारे पास कम भूमि है, आजीविका और आय के सीमित स्रोत हैं और अगर हमारी संपत्ति हमारे बच्चों के बीच वितरित की जाएगी तो प्रत्येक बच्चे को बहुत कम मिलेगी। शराब की लत छोड़ना भी एक मुद्दा है जिस पर हमें काम करना है। मैं यह कहना चाहूंगा कि कलेक्टर के रूप में मेरे कार्यकाल के दौरान पोशीना में पांच पुलों को मंजूरी दी गई है और उन्हें बनाया जा रहा है। नेट कनेक्टिविटी का सवाल शायद अगले दो महीनों में हल हो जाएगा। अन्य नई अनुमोदित योजनाएं डेयरी उत्पादन और लिफ्ट सिंचाई हैं। शिक्षा के लिए चंद्राना के लिए एक आश्रम शाला को मंजूरी दी गई है। पेयजल के लिए 136 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं और तालुका के आधे गांव हैंडपंप मुक्त होंगे क्योंकि शहरों की तरह पाइपलाइनों से पानी की आपूर्ति की जाएगी। आंगनवाड़ी को नियमित रूप से कार्य करना चाहिए। आंगनवाड़ी सार्वजनिक सेवाओं का हिस्सा हैं और निजी संपत्ति नहीं हैं इसलिए इन्हें नियत रूप से नियमित रूप से कार्य करना चाहिए।

श्री महेश पटेल (विकसत के उप निदेशक) ने पोशीना में विकसत की भूमिका के बारे में बात की। इसका उद्देश्य समुदाय के जल, जंगल और भूमि अधिकारों की रक्षा करना और उनकी आजीविका को बढ़ाने के लिए समुदाय को सक्षम करना है। इसके तहत इस महिला समूह के रूप में ऋण और बचत सोसाइटी का गठन किया गया है और उनकी आजीविका को मजबूत करने के लिए उत्पाद की बिक्री के लिए एक कंपनी पंजीकृत की गई है।

सुश्री जयाबेन वाघेला, उप प्रबंध निदेशक, गुजरात राज्य महिला सेवा सहकारी संघ लिमिटेड ने समापन भाषण दिया जिसमें उन्होंने महिलाओं को उठने! जागने! की जरूरत पर ज़ोर दिया और नारेबाजी के माध्यम से एक समूह के रूप में संगठित होने की आवश्यकता पर बल दिया। महिलाओं को एक वर्ष में 365 दिनों में से केवल एक दिन दिया गया है। लेकिन हम भी सवाल क्यों नहीं करते, हमें केवल एक दिन क्यों दिया गया है। हम क्यों नहीं बोलती हैं, इस प्रश्न को आज पूर्व के वक्ताओं ने उठाया है। हमें बोलने और हमारी मांग पैदा करने की जरूरत है। हमारे पास कई सरकारी योजनाएं हैं, लेकिन हम इसके कार्यान्वयन के लिए पूछने या मांगने के लिए अपनी आवाज नहीं उठाती हैं। हमें बैंक जाने के लिए, विभिन्न सरकारी विभागों में जाने और सेवाओं की मांग करने, आंगनवाड़ी में जाने और हमारे हकों की मांग करने के लिए अच्छी तरह से सूचित किया जाना चाहिए। मांग करने के लिए हमें जागरूक और अच्छी तरह से पता होना चाहिए। यहाँ हममें से ज्यादातर माताएं बैठी हुई हैं। यदि हम माता के रूप में कुपोषित हैं तो बच्चों के कुपोषित होने की संभावना है। आदिवासी समाज के पिछड़ेपन के कारणों में से एक गरीब होना या खराब स्वास्थ्य होना है। आदिवासी समाज की प्रगति के लिए हम सब जो यहां बैठे हैं उनको जागरूक होने और पर्याप्त सशक्त होने की जरूरत है ताकि हमारी हकदारी के बारे में ठीक से पता हो और हम मांगें पैदा कर सकें। इसलिए मैं आप सबसे आगे आने और अपने हाथों में विकास की लगाम लेने और आगे बढ़ने के लिए अनुरोध करती हूं।

अंत में सभी गणमान्य लोगों, प्रतिभागियों और गांवों की महिलाओं, विभिन्न सीएसओ और सरकारी विभागों के सभी मेहमानों, सभी स्टालों लगाने वालों, आयोजन टीम और स्थल प्रशासन का धन्यवाद ज्ञापित किया गया। ■

एनजीओ बोर्ड मीटिंग के दौरान ध्यान में लेने वाले मुद्दे

एनजीओ बोर्ड को कड़ी मेहनत और निरंतर लगे रहने की सराहना तो करनी ही चाहिए, लेकिन उसे बेहतर प्रदर्शन और मानकों पर ध्यान केंद्रित करने में भी कुछ समय लगाना चाहिए। बोर्ड आमतौर पर बोर्ड बैठक के दौरान कार्यकारी अधिकारियों/प्रबंधन के साथ ही बातचीत करता है, जिसमें कभी-कभी क्षेत्र दौरा भी शामिल होता है जो बोर्ड मीटिंग को प्रभावी बनाने के लिए आवश्यक होता है। प्रत्येक बोर्ड मीटिंग के एजेंडा में निम्नलिखित नियमित मुद्दे शामिल हो सकते हैं। एकेआरएसपी-आई के श्री अपूर्व ओझा ने 9 बिन्दुओं का सुझाव दिया है जिनका बोर्ड मीटिंग का आयोजन करते समय पालन करना चाहिएः

1. सभी सांविधिक अनुपालन और उनकी समयबद्धता पर वार्षिक अद्यतन विवरण।
2. एचआर/ओडी अपडेट जिसमें दुर्घटना, लिंग अनुपात और नेतृत्व विकास पर जानकारी शामिल होती है।
3. संगठन के स्थायित्व के लिए योजनाः कॉर्पस या संपत्ति या आय के स्रोत।
4. दाताओं की यथोचित तत्परताः ऐसे कई कॉर्पोरेट और परोपकारी हैं जिनकी वजह से गैर सरकारी संगठन की प्रतिष्ठा को जोखिम होता है। बोर्ड द्वारा अनुमोदित या शामिल मानक प्रक्रिया तैयार की जा सकती है जो यह सुनिश्चित करेगी कि धन प्राप्त करने की जल्दी में गलत भागीदारों का चयन नहीं हो जाए।
5. विषयों / भौगोलिक क्षेत्रों पर स्टॉफ सदस्यों द्वारा नियमित प्रस्तुतियां। यह न केवल बोर्ड को बढ़ते संगठन के विभिन्न आयामों को समझाता है, बल्कि यह कर्मचारियों के विकास के लिए भी अच्छा है।
6. वार्षिक खातों को अंतिम रूप देने के दौरान बोर्ड, विशेष रूप से लेखा परीक्षा / वित्त समिति द्वारा सांविधिक लेखा परीक्षकों के साथ सीधी बातचीत करनी चाहिए।
7. कर्मचारियों की शिकायत निवारण, कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न, पूर्वाग्रह से संबंधित मुद्दों, राजनीतिक दबाव / हस्तक्षेप आदि से संबंधित किसी भी महत्वपूर्ण घटना पर अद्यतन विवरण।
8. परियोजनाओं / कार्यक्रमों की सभी आंतरिक / बाहरी मूल्यांकन रिपोर्टों के तैयार होने पर साझा करना।
9. विभिन्न भौगोलिक क्षेत्रों को कवर करते हुए अनिवार्य वार्षिक क्षेत्रीय दौरा करना।

उन्नति

उन्नति

विकास शिक्षण संगठन

जी-1, 200, आज़ाद सोसायटी, अहमदाबाद-380015

फोनः 079-26746145, 26733296 फैक्सः 079-26743752 email: sie@unnati.org वेबसाइटः www.unnati.org

राजस्थान क्षेत्रीय कार्यालय

650, राधाकृष्णन पुरम, लहरिया रिसोर्ट के पास, चौपासनी-पाल बाई पास लिंक रोड, जोधपुर-342014, राजस्थान

फोनः 0291-3204618 email: jodhpur_unnati@unnati.org

इस बुलेटिन के लेखों में व्यक्त विचार लेखकों के अपने हैं।

दीपा सोनपाल, रमेश पटेल : ईमेलः sie@unnati.org, publication@unnati.org

अनुवादः आर. के. गुप्ता

मुद्रकः प्रिन्टविझन, अहमदाबाद

केवल सीमित वितरण के लिए

आप लोक शिक्षण व प्रशिक्षण के लिए विचार में प्रकाशित सामग्री का सहर्ष उपयोग कर सकते हैं। कृपया सौजन्य का उल्लेख करना न भूलें और साथ ही अपने उपयोग से हमें अवगत करवायें ताकि हम भी उससे कुछ सीख सकें।